सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 136, नई दिल्ली । शनिवार, 27 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी।

03 राष्ट्रपति मुर्मू ने सेंट्रल स्कूल 9वीं के छात्रों ली क्लास

06 गुरु का महत्व

08 पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा पर सैकड़ों ट्रक रोके गए हैं

दिल्ली की जनता के वाहन जो परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा अपने बल का दुरुपयोग कर उठवाकर अपने प्रिय वाहन स्क्रैप डीलरों को सुपुर्द किए गए थे उनमें से अधिकतर वाहन स्क्रैप डीलरों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगाई गई

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में यह बात आज भी सभी को याद होगी दिल्ली में दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व आयुक्त एवम्-तत्काल में प्रधान सचिव उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत आशीष कुंद्रा एवम्-विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम द्वारा जनता के वाहनों को प्रदुषण मुक्त दिल्ली बनाने का नाम लेकर अपने बल का दुरुपयोग कर वाहन उठवाकर अपने प्रिय वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द कर दिए थे जिनमे से किसी का भी अधिकृत कार्यालय दिल्ली क्षेत्र में नही था। **हमने तब भी परिवहन विभाग से**

1. यह जानने की कोशिश की थी की किस आधार पर विभाग ने इन्हे वाहन सुपुर्द करने के लिए चुना पर किसी ने जवाब देना उचित नहीं समझा था
2. हमने उसके बाद विभाग से यह सूचना मांगी की जो वाहन आप अपने प्रिय वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द कर रहे हैं क्या सच में वह स्क्रैप हो रहे हैं, तब भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया
3. हमने उन्हें बताया कि जो वाहन आपने अपने प्रिय स्क्रैप डीलर को सुपुर्द किया है उसका टोल टैक्स अन्य राज्य में कटा है उस पर भी उन्होंने कोई जवाब देना या कार्यवाही करना उचित नहीं समझा था।

कारण वह उनके प्रिय थे। आप सबको सुचित कर रहे हैं की जो कार्य जनहित में दिल्ली परिवहन विभाग के इन दो अधिकारियों को समय रहते करना चाहिए था वह कार्य सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया और दिल्ली के इन दोनो अधिकारियों के प्रिय वाहन स्क्रैप डीलरो में से अधिकतर वाहन स्क्रैप डीलरो को वाहन स्क्रैप के लिए ना देने के सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए। **कारण** सरकारी और विभागीय वाहनों जो इन वाहन स्क्रैप डीलरो द्वारा ई ऑक्शन (नीलामी) में स्क्रैप करने के लिए प्राप्त किए थे उन का पूर्ण ब्योरा उपलब्ध नहीं करवाया साथ ही जो आडिट रिपोर्ट 31 मार्च तक जमा करवानी थी वह भी जमा नहीं करवाई। **अब प्रश्न यह फिर से उठता है की जो वाहन परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा इन्हे स्क्रैप करने के लिए सुपुर्द किए थे वह कहा है और उनका क्या किया ?** इसका जवाब तो अब **दिल्ली में कार्यरत उच्च पदों पर आसीन यह दो ही**

अधिकारी दे सकते है या फिर इन्हे इन पदों पर आसीन करने वाले दिल्ली के मुख्य सचिव या माननीय उपराज्यपाल।

जनहित और जनता की जानकारी के लिए जिन अधिकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ई नीलामी के लिए प्रतिबंधित किया गया है उन के नाम

1. Chunk Recycling India Private Limited
2. PKN Motor Screppers Private Limited
3. Indian Motors
4. Bharat Motors
5. Nirvana Screppers
6. Saral Auto Scraping India Private Limited
7. Global Ultra Tech

दिल्ली की जनता के लिए विशेष सूचना प्रतिबंधित वाहन स्क्रैप डीलरो में से कुछ वाहन स्क्रैप डीलरो को दिल्ली एमसीडी ने भी परिवहन विभाग की तरह दिल्ली की जनता के वाहनों को उठाने के लिए अधिकृत किया हुआ है अगर इस लिस्ट में शामिल कोई आपके वाहन को उठाने या एमसीडी का अधिकारी उठा कर इन्हे सुपुर्द करने का प्रयास करे तो तत्काल दिल्ली पुलिस को सूचना देकर उसके खिलाफ कार्रवाई करे और साथ ही हमे 9811902095 पर सूचित करे, क्योंकि यह सभी वाहन स्क्रैप डीलर अब आपका वाहन नहीं उठा सकते और ना ही कानूनी तरीके से स्क्रेप कर सकते है। आप सभी इस जानकारी की सत्यता को नीचे दिए गए लिंक पर जांच सकते है की अब इन्हे ऑपरेशन यानी वाहन स्क्रैप करने से बाहर कर दिया गया है **और 90 दिन के अंदर राज्य परिवहन विभाग/ राज्य सरकार जिन्होंने इन्हे पंजीकृत किया था वह इनके लाइसेंस रद्द कर देंगे अन्यथा 90 दिनों के बाद यह कार्य भी सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय कर देगा।** जनता से हमारी अपील है अपने वाहन स्क्रैप करवाने से पहले इस बात की पुष्टि कर ले की आपका वाहन स्क्रैप होने के बाद आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट जारी हो गया या नही
https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/welcome.xhtml

दिल्ली में मोहल्ला बसों के रूट निर्धारण के लिए AI का इस्तेमाल, आईआईटी दिल्ली की मदद से तैयार होगा मार्गों का डिजाइन

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा– सार्वजनिक परिवहन में एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग दिल्ली के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। हम मोहल्ला बस रूट को अंतिम रूप देने में एटीआइ की भी मदद ले रहे हैं। कम सेवा वाले और अधिक फुटफॉल वाले क्षेत्रों की पहचान करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा मोहल्ला बस नेटवर्क स्थायी रूप से संचालित भी हो।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार मोहल्ला बसों के मार्गों को अंतिम रूप देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर रही है। आईआईटी-दिल्ली के सहयोग से, सरकार प्रमुख क्षेत्रों को इंगित करने और बस मार्गों को डिजाइन करने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स और एआई-संचालित समाधानों का उपयोग करेगी।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने मार्गों की पहचान करने और क्षेत्र में मोहल्ला बसों के संचालन की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) को भी तैनात किया है। 32 सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) की एक टीम बनाई गई है, जिसे चार जोन में विभाजित किया गया है, प्रत्येक जोन में चार एटीआई की दो टीमें हैं। ये टीमें मार्गों पर नौ मीटर मोहल्ला बसों के संचालन की व्यावहारिक चुनौतियों को समझने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करेंगी। टीम इन क्षेत्रों में नए मार्ग शुरू करने पर जनता से इनपुट भी जुटाएगी।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा "सार्वजनिक परिवहन में एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग दिल्ली के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। हम मोहल्ला बस रूट को अंतिम रूप देने में एटीआई की भी मदद ले रहे हैं। कम सेवा वाले और अधिक फुटफाल वाले क्षेत्रों की पहचान करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा मोहल्ला बस नेटवर्क न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाए बल्कि कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से संचालित भी हो। यह पहल दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

मोहल्ला बस नेटवर्क निर्धारण के लिए पद्धति

आपूर्ति एवं मांग मॉडल निर्माण

आईआईटी-दिल्ली ऐसे सभी ओरिजिन और गंतव्य की पहचान करने के लिए एक मॉडल विकसित करेगा जहां यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद वर्तमान में कम बसें चल रही हैं। यह माडल वर्तमान पारगमन नेटवर्क और कनेक्टिविटी का मूल्यांकन करने के लिए रियल वर्ल्ड ट्रैवल टाइम डेटा का उपयोग करेगा। यह स्थानों के बीच यात्रा की आसानी निर्धारित करने और कम सेवा वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए परिवहन एजेंसियों और गूगल मानचित्र सहित यात्री सूचना प्लेटफार्मों से पारगमन और यात्रा समय डेटा भी कैप्चर करेगा।

नेटवर्क-वाइड ट्रैवल डिमांड मॉडल

यह माडल स्थान-आधारित सेवाओं और जीपीएस-सक्षम ऐप्स से यात्रा डेटा एकत्र करेगा तथा इसे मूल-गंतव्य मैट्रिक्स प्रारूप में परिवर्तित करेगा। यात्रा पैटर्न का विश्लेषण करने और उच्च-फुटफाल वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए यह दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से सवारियों के डेटा का विश्लेषण करेगा।

रूट नेटवर्क डिजाइन

विकसित माडल का उपयोग करके, आईआईटी-दिल्ली मोहल्ला बसों के लिए एक कुशल रूट नेटवर्क डिजाइन करेगा। इसमें एआई/मेटाहेरिस्टिक्स-आधारित रूटिंग एल्गोरिदम शामिल होगा जो परिवर्तनीय यात्री भार को संभालने, कवरेज को अधिकतम करने और मार्ग व्यवहार्यता और उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।एल्गोरिदम मौजूदा पारगमन नेटवर्क, यात्रा की मांग, परिचालन संबंधी बाधाओं और ड्राइविंग की तुलना में सामान्यीकृत लागत सहित उपयोगकर्ता अनुभव कारकों पर विचार करेगा।

निगरानी

मार्ग डिज़ाइन के बाद, आइआइटी-दिल्ली मार्गों की निगरानी में दिल्ली परिवहन विभाग की मदद भी करेगा।इसमें रियलटाइम डेटा संग्रह और विश्लेषण महत्वपूर्ण होगा।

समावेशी और जमीनी दृष्टिकोण

एआइ का लाभ उठाने के अलावा, दिल्ली सरकार मोहल्ला बसों के रूट निर्धारण के लिए क्षेत्र के विधायकों, स्थानीय लोगों के इनपुट और परिवहन विभाग की तकनीकी टीम द्वारा 30-दिवसीय व्यापक जमीनी मूल्यांकन के दौरान एकत्रकिए गए डेटा का भी इस्तेमाल कर रही है।

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर देगी छूट, एलजी के पास भेजा गया प्रस्ताव; जानें क्या है प्रावधान

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा इस कदम का उद्देश्य पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा इस कदम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।

प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा गया

इसके लिए जो प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। उसके अनुसार नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20% की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15% की होगी।

नए वाहनों के मामलों में 15 प्रतिशत की छूट

नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15% की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10% की छूट मिलेगी। हालांकि दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक खरीद-फरोख्त किया जा सकता है।

बारिश बनी आफत: किशनगंज रेलवे अंडरपास की दीवार गिरी, यातायात हुआ प्रभावित

दिल्ली में शुक्रवार सुबह किशनगंज रेलवे अंडरपास की दीवार गिर गई। बारिश होने के कारण यह दीवार गिरी है। वहीं दीवार गिरने की सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। बताया गया कि दीवार गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही यहां पर यातायात को पूर्ण रूप से सुचारु कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सुबह हुई वर्षा के कारण किशनगंज रेलवे अंडरपास की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। बताया गया कि आजाद मार्केट से प्रताप नगर, शास्त्री नगर जाने वाले मार्ग पर यह हादसा हुआ है। उधर, सूचना मिलने के बाद नगर नगम की टीम मौके पर पहुंची।

भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स का योगदान

डॉ. अंकुर शरण

लॉजिस्टिक्स वह अदृश्य धागा है जो किसी भी उद्योग की बुनियाद को मजबूत बनाता है। यह न केवल उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण को सुगम बनाता है, बल्कि उपभोक्ता तक उत्पाद को समय पर और सुरक्षित रूप से पहुँचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश में, लॉजिस्टिक्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

उत्पादन और वितरण का संगम

उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तैयार उत्पाद के वितरण तक, लॉजिस्टिक्स की अहम भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पर, ऑटोमोबाइल उद्योग में विभिन्न घटकों का समय पर संयंत्र में पहुँचना आवश्यक होता है ताकि उत्पादन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। अगर इन घटकों की आपूर्ति में थोड़ी भी देरी होती है, तो पूरी उत्पादन प्रक्रिया ठप हो सकती है, जिससे समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है।

आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन

लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) उद्योग इसका एक उत्तम उदाहरण है। इस उद्योग में उत्पादों की समय पर आपूर्ति आवश्यक होती है, क्योंकि उपभोक्ता जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की मांग करते हैं। लॉजिस्टिक्स की सहायता से इन उत्पादों को समय पर उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे उनकी ताजगी बनी रहती है और उपभोक्ता संतुष्ट होते हैं।

ई-कॉमर्स का उदय

डिजिटल युग में ई-कॉमर्स उद्योग का विस्तार हुआ है, और इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ उपभोक्ताओं को समय पर उत्पाद पहुँचाने के लिए लॉजिस्टिक्स का सहारा लेती हैं। यहाँ तक कि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी ये कंपनियाँ अपनी सेवाएँ प्रदान कर पा रही हैं, जो कि केवल प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के कारण संभव हो पाया है।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, कच्चे माल की समय पर आपूर्ति और तैयार उत्पादों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। यहाँ पर भी लॉजिस्टिक्स का महत्व नजर आता है।

लॉजिस्टिक्स की महत्ता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह किसी भी उद्योग के लिए जीवनदायिनी है, जो न केवल उद्योग को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। तेजी से बढ़ते भारत में, जहां हर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, लॉजिस्टिक्स का प्रभावी प्रबंधन उद्योगों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास की भी अपार संभावनाएं हैं, जो भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को और भी तेजी से बढ़ाने में सहायक होंगी।

श्री यशपाल सिंह नेगी: एक प्रेरणास्रोत

मेरे मेंटर, श्री यशपाल सिंह नेगी, जो एक प्रतिष्ठित सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं, ने मुझे कॉर्पोरेट उद्योग में लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन संभालने का अवसर दिया।

उनका कहना है कि ₹सर्वश्रेष्ठ सप्लाई चेन प्रोफेशनल माँ होती है, जो अपने रसोई के लिए आवश्यक सामग्री को सटीक मात्रा में जानती है। वह जानती है कि क्या खरीदना है और इसे सही समय पर न्यूनतम लागत में कैसे प्राप्त करना है।"

सप्लाई चेन प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स किसी भी उद्योग की रीढ़ हैं। श्री नेगी का यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि सफल सप्लाई चेन प्रबंधन की कुंजी सही योजना, समय की पाबंदी, और लागत की दक्षता में निहित है। उनके अनुभव और दृष्टिकोण ने मुझे इस क्षेत्र में गहराई से समझने और अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा दी है।

(लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ)
ankur.supplychain@gmail.com

इनसाइड

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें.अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें.इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं. इस आसन को किसी भी आयु और अवस्था की महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. दंडासन करने से कंधों में खिंचाव की दिक्कत कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और पाचन शक्ति बढ़ती है।

हिमा दास भारत की बेटी जिसने 19 साल की आयु में देश के नाम किये पांच स्वर्ण पदक

पांच स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाली हिमा दास पहली भारतीय महिला हैं, यह उपलब्धि हिमा ने मात्र 19 वर्ष की आयु में हासिल की । हिमा दास को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा शुरुआती जीवन में फुटबॉलर बनना चाहती थी, लेकिन पीटी टीचर ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें एथलेटिक बनने की सलाह दी।

हिमा दास' भारत की इस बेटी को आज किसी के परिचय की जरुरत नहीं है। संसाधनों की कमी के बावजूद भारत को दुनिया के सामने गर्वित होने का अवसर देने वाली हिमा दास का शुरुआती जीवन काफी संघर्षमय था, हिमा ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की और एक नया इतिहास बनाया। हिमा का पूरा परिवार खेती पर निर्भर था,इनके पिता का नाम रंजीत और माता का नाम जोनाली हैं। हिमा ने अपनी शुरूआती शिक्षा धींग हाई स्कूल और नवोदय विद्यालय से पूरी की। स्कूल में हिमा की रूचि फुटबॉल में थी उनके स्कूल टीचर ने उनकी फुर्ती और तेज दौड़ने क्षमता देखकर एथलेटिक्स में हाथ आजमाने की सलाह दी। स्थानीय प्रतियोगिताओं में हिमा ने बेहतर प्रदर्शन किया और गुवाहाटी स्टेट चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया जिसमें उन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इसके बाद हिमा ने नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया।

ट्रेनिंग में जाने के लिए नहीं थे पैसे

हिमा का परिवार उनकी ट्रेनिंग का खर्च उठाने में असमर्थ था, कोच निपुण दास ने उनके अभिभावकों से बात की, ट्रेनिंग सेंटर उनके घर से 150 किलोमीटर दूर था। पिता रंजीत ने सिर्फ यह सोचकर बेटी को ट्रेनिंग में जाने दिया कि ट्रेनिंग सेंटर में हिमा को अच्छा खाना मिलेगा। ट्रेनिंग सेंटर वालों को हिमा में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के गुण दिखाई दे रहे थे इसलिए उन्होंने हिमा का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली। हिमा के पिता ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बेटी को अच्छे जूते दिलाने के लिए खर्च कर दिया, 1200 रुपये के जूते उनके लिए बहुत महंगे थे। कड़ी मेहनत के बल पर हिमा आगे चल कर उसी जूते की ब्रांड अम्बेसडर बन गई।

देश को दिलाया स्वर्ण पदक

कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की प्रतियोगिता में छठा स्थान प्राप्त करने के बाद हिमा ने फ़िनलैंड में स्वर्ण पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया। आईएएएफ़ वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 400 मीटर की स्पर्धा मात्र 51: 45 सेकेण्ड में पूरी की। यह कारनामा उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में किया, इतनी कम उम्र में यह रिकॉर्ड बनाने वाली वह पहली महिला भारतीय खिलाड़ी हैं।

महिलाएं फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान के लिए अपनाएं ये टिप्स, कभी नहीं होगी पैसों की दिक्कत

आजकल की मॉर्डन लाइफस्टाइल में ज्यादातर महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पसंद करती हैं. हालांकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं भी कई बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial security) को अवॉयड कर देती हैं. जिसके चलते भविष्य में आपको कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं. फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए काफी एफर्ट की जरूरत पड़ती है. ऐसे में ऑफिस और घर में उलझी महिलाएं अक्सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी से दूर भागती नजर आती हैं. वहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में अहम भूमिका निभाती है. ऐसे में कुछ गलतियों को नजरअंदाज करके महिलाएं भी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन्श्योर कर सकती हैं.

खुद मैनेज करें फाइनेंस

जॉब करने वाली अधिकतर महिलाएं अपना फाइनेंशियल चार्ज पार्टनर को सौंप कर फ्री हो जाती हैं. जिसके चलते न सिर्फ पार्टनर पर डबल रिपॉन्सिबिलिटी आ जाती है बल्कि आप खुद भी अपने फाइनेंस से अंजान रहती हैं. ऐसे में पार्टनर से हेल्प लेकर आप अपने फाइनेंस खुद मैनेज कर सकती हैं. वहीं अगर आप चाहें तो किसी फाइनेंस एक्सपर्ट की भी मदद ले सकती हैं.

करियर पर फोकस करें

कई बार घर की परेशानियों से डील करने के लिए महिलाओं को जॉब से समझौता करना पड़ता है. जिससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर भी खतरा मंडराने लगता है. ऐसे में घर की परेशानियां सॉल्व करने के लिए आप नौकरी से ब्रेक ले सकती हैं. मगर हर परिस्थिति में करियर को नजरअंदाज बिल्कुल न करें. इससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी.

इंवेस्टमेंट को न करें अनदेखा

वर्किंग वुमन अक्सर सेविंग को लेकर काफी केयरलेस होती हैं. ऐसे में महिलाएं अपना सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ में इंवेस्ट करना पसंद करती हैं. हालांकि महिलाओं के लिए इक्विटी फंड या म्युअचल फंड में इंवेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन होता है. इससे आपको को एफडी के कम्पेयर में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. लेकिन कोई भी इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करना बेहतर होता है.

इंश्योरेंस पॉलिसी लें

महिलाओं को वर्तमान समस्याओं से निपटने के साथ-साथ भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए. ऐसे में इश्योरेंस पॉलिसी लेकर आप अपने और फैमली के लिए एडवांस प्लानिंग कर सकती हैं. वहीं लाइफ इश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस करवाकर आप फैमली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इन्श्योर कर सकती हैं.

रिटायरमेंट प्लानिंग करें

जॉब के दौरान ज्यादातर महिलाएं रिटायरमेंट प्लानिंग को अवॉयड कर देती हैं. जिसके चलते रिटायरमेंट के बाद महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में रिटायरमेंट के लिए अभी से इंवेस्टमेंट करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं.

हर महिला को सफलता पाने के लिए अपनाने चाहिए ये 6 मंत्र ! सभी समस्याएं होंगी दूर

एक महिला होने के नाते समाज और परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर होती है. समाज और परिवार की अपेक्षाओं और मांगों को पूरा करते करते महिलाएं खुद की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने में पीछे रह जाती हैं. हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी अलग सी हों, लेकिन यह पहचानना भी जरूरी है कि ऐसी जिम्मेदारियां खुद आपके लिए विनाशकारी तो नहीं हैं. दरअसल, यह जरूरी नहीं कि आप समाज की हर उम्मीदों पर हमेशा खड़ी ही उतरें, क्योंकि खुद का ख्याल सबसे पहले आप खुद ही रख सकती हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि महिलाओं को जीवन में किन 6 तथ्यों को जानना जरूरी है.

महिलाओं को जरूर जाननी चाहिए ये 6 जरूरी बातें

लोगों को खुश रखने की आदत न बनाएं- लोगों के प्रति दया भाव रखना और लोगों को हर वक्त खुश रखना, इन दोनों परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर होता है. महिलाओं को यह ध्यान देना जरूरी है कि लोगों को हर वक्त खुश रखने की आपकी आदत कहीं आपके खुद की जिंदगी को मुश्किल में तो नहीं डाल रही.

यूनीक बनें- फैशन, ट्रेंड, टिकटॉक, इंस्टाग्राम आदि के चक्कर में महिलाएं अपना पर्सनल ओपीनियन भूल जाती हैं. लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रेंडी बने रहने के फिराक में कहीं आपका अपना यूनीक पर्सनैलिटी खो ना जाए. इसलिए खुद की राह अपने से बनाएं और लाइफ को एक्सप्लोर करें.

फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनें- घर परिवार चलाने के लिए महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना कि एक आदमी. यही नहीं, अगर आप फाइनेंशियली दूसरे पर डिपेंड रहेंगी तो आप अपने लाइफ की जरूरी प्रायोरिटीज को हैंडल नहीं कर पाएंगी और खुद की जिंदगी भी आपकी अपनी नहीं रहेगी.

स्किल डेवलप करें- एक ही चीज में जिंदगी भर बने रहने से बेहतर है कि आप खुद के स्किल को डेवलप करती रहें. नई नई चीजों को सीखें और खुद को अधिक से अधिक एक्सप्लोर करें. ऐसा करने से भविष्य को लेकर आप बेहतर प्लान बना सकेंगी और चिंताओं से मुक्त रहेंगी.

राष्ट्रपति मुर्मू ने सेंट्रल स्कूल 9वीं के छात्रों की ली क्लास

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन स्थित डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय विधालय के 9 वीं कक्षा छात्राओं की क्लास ली। उन्होंने बच्चों को पढाया और उनसे बातचीत भी की। राष्ट्रपति के द्वारा बच्चों को पढाये जाने को लेकर दिल्ली की 41 साल पुरानी संयुक्त अनुसूचित जाति/जन जाति शिक्षक मंच के एनपीपीएस राम किशन पूनिया ने x ट्विटर हैंडल पर राष्ट्रपति से अपील तक कर डाली है कि वह शिक्षा व्यवस्था को करीब से देखना चाहती है तो एक दिन MCD औरनDOE स्कूल में भी जरूर पढ़कर एक नया संदेश देने की कृपा करें। तो इन शैक्षिक संस्थानों में भी सुधार हो जाएगा।

प्रदूषण जांच केंद्रों की हडताल का तोड निकाला, खत्म

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राजधानी दिल्ली के प्रदूषण जांच केंद्रो की लंबे समय से चली आ रही हडताल का तोड निकाल लिया है। बता दें कि इस समय गाडियों के प्रदूषण जांच केंद्रो को दिल्ली पैट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अहवाहन पर जांच दरों में बढोतरी की मांग को लेकर हडताल चल रही है। इस हडताल की वजह से गाडियों की प्रदूषण जांच में 86 फीसदी की कमी आई है। और प्रदूषण का स्तर भी दिनो दिन दिल्ली में बढ रहा है। प्रदूषण जांच केंद्रो के संचालको की हडताल और दमगई के आगे झुकने की बजाए दिल्ली सरकार ने मैट्रो स्टेशनों के पार्किंग लाइट्स और CNG स्टेशनों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और IGL को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा हडताल में शामिल प्रदूषण जांच केंद्रो के संचालको के.खिलाफ भी परिवहन विभाग कडी कारवाई करने जा रहा है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के इस फैंसले से दिल्ली में पैट्रोल पंपा पर बने प्रदूषण जांच केंद्रो पर चल रही हडताल करने वाली लाबी का माथा ठिकाने आ गया है।अब उन्होने भी पैट्रोल पंपों पर बने जांच केन्द्रो पर चल रही हडताल को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया है। बता दें कि 15 जुलाई से प्रदूषण जांच केंद्रो की हडताल चल रही थी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मीटिंग के बाद दिल्ली पैट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हडताल को तुरंत प्रभाव से खत्म करने का फैंसला किया है। अब राजधानी दिल्ली वाले अपनी गाडियों की प्रदूषण जांच को इन्हीं केंद्रो पर करवा सकेगे।

नए पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी परिवहन वाहनों के लिए कर में 15% की छूट; डीजल परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 10% की छूट

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपोज़िट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है।

एक बयान में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, ₹इस क़दम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से, हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।₹

इस प्रस्ताव को माननीय उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद, नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की ख़रीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20% की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15% की होगी। नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15% की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की ख़रीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10% की छूट मिलेगी। हालाँकि, दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगी।

उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपोज़िट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक ख़रीद-फरोख्त किया जा सकता है।

दोनों भाई-बहन को साल 2017 में उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था

सुषमा रानी

नई दिल्ली :केजरीवाल सरकार से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले एमबीबीएस छात्र अक्षित शर्मा को 25.55 लाख रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसे मंजूरी दी। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र अक्षित और अक्षिता से मुलाक़ात भी की। दोनों को साल 2017 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था और पिछले सालों में भी केजरीवाल सरकार अपने स्कीम के तहत इन दोनों छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देती आई है।

इस मौक़े पर उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, केजरीवाल सरकार देश-समाज के लिए बहादुरी दिखाने वाले बच्चों के साथ खड़ी है। इन बच्चों की बहादुरी पूरे देश के लिए मिसाल है।

बता दे कि, केजरीवाल सरकार अपने स्कीम के तहत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले दिल्ली निवासी छात्रों को उनके उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को जो देश के किसी उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे है, उन्हें उनके कोर्स का शत प्रतिशत ट्यूशन फ़ीस अनुदान में मिलता है ताकि वो बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सके।

साथ ही इन छात्रों को सालाना स्टेशनरी के लिए 5000 रुपये भी मिलते है। साथ ही इस

स्कीम में उन छात्रों को एक स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस के तहत प्रतिमाह 2500 दिए जाते है, जिनके पेरेंट्स की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।

केजरीवाल सरकार के दिल्ली हाईर एजुकेशन एड ट्रस्ट के तहत छात्रों को ये अनुदान दिया जाता है। इसी के अंतर्गत दिल्ली निवासी अक्षित शर्मा, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था। उन्हें एमबीबीएस की फ़ीस और स्टेशनरी के लिए 25.55 लाख रुपये का अनुदान देने को मंजूरी मिली है। साथ ही हाल ही में एलएलएम पूरा करने वाली उनकी बहन अक्षिता शर्मा को भी केजरीवाल सरकार ने ट्यूशन फ़ीस के लिए पिछले सालों में अनुदान देते आई है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खिचड़ीपुर में कावड़ शिविर का किया उद्घाटन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शिव भक्त कांवड़ियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस कड़ी में शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा खिचड़ीपुर में 'खिचड़ीपुर शिव कांवड़ सेवा समिति' शिविर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में करीब 185 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने सभी जिला प्रशासन को कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर जरूरी कदम सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हर वर्ष भगवान भोलेनाथ के भक्त और कावड़ियों के लिए शिविर कैंप लगाए जाते हैं। यह शिविर कैंप पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। इसके अलावा इन कैंपों के अंदर मेडिकल से लेकर पानी, सोने के लिए बेड, कूलर और शौचालय की समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार, त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरोलिया, कल्याणपुरी से पार्षद बंटी गौतम , समिति के अध्यक्ष सुरज मल वर्मा ,विश्वास नगर विधानसभा के अध्यक्ष दीपक सिंगला, सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम भट्ट समेत अन्य लोग मौजूद थे।

सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जल लेने जाते है। इसके

बाद लोग अपने-अपने शहर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर दिल्ली सरकार राजधानी में जगह-जगह कांवड़ शिविर लगाती है। कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के रुकने और आराम करने के लिए हर जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। वहीं इस साल उनकी सुविधा के लिए स्थानीय डिस्पेंसरियों को शिविरों से जोड़ा गया है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए कैट्स एंबुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पतालों को कांवड़ियों के इलाज के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपाल राय ने आगे कहा कि चूंकि बारिश की अधिक संभावना है। इसलिए बिस्तर और मेजों के साथ वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि 185 शिविरों में कम से कम 10 हजार श्रद्धालु आसानी से रह सकते हैं। सावन में बारिश की अच्छी संभावना है, इसलिए हमने शिविर में वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की है। साथ ही यहां डॉक्टर को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, ₹मेडिकल टीमें 24 घंटे शिविर में मौजूद रहेंगी और तीन अलग-अलग शिफ्टों में काम करेंगी। कावड़ शिविर के बाहर एंबुलेंस भी तैनात की गई है। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य चोट की स्थिति में, व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाया जाएगा।"

डी पी यादव पुनः चुने गये एनयुबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

नई दिल्ली। दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ (NUBC) की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद, एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डीपी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संस्थागत ढांचे और प्रारूप के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस विशेष अवसर पर महासंघ को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल गया. दरअसल इस कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी यादव को महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद सभागार

में बैठे सभी सदस्यों में एक अलग ही जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला सभी ने गर्मजोशी के साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ना केवल जोरदार स्वागत किया बल्कि अपने संबोधन के माध्यम से संस्था की आगे की लड़ाई में अपना योगदान निभाने की प्रतिबद्धता का भी संकल्प लिया। इस मौके पर महासंघ के अन्य राज्यों से आये हुए सभी पदाधिकारियों व सभी सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव की उपस्थिति में केक काटकर उनके जन्मदिन का भी जश्न मनाया। सभागार को संबोधित करते हुए नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव ने भी संस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही उन्होंने संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और इसके माध्यम से पिछड़े और वंचित लोगों की आवाज को भी संबंधती पटल पर उठाने पर जोर दिया। इस मौके पर संस्था से जुड़े कई वर्तमान व पूर्व सांसद, विधायक के अलावे प्रधान मुकेश यादव, इंजीनियर अनिल यादव, सुनहरी लाल, सरजीत यादव, सुबोध यादव, अशोक यादव (काशी) सहित सेंकड़ों की संख्या मे लोग उपस्थित रहे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रभात झा का आज सुबह तड़के दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर उनका इलाज चल रहा था। एमपी के सीएम और मंत्रियों ने गहरा शोक प्रकट किया है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रभात झा का आज सुबह निधन हो गया। उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था।

भोपाल के बंसल अस्पताल में चल रहा था इलाज

मेदांता से पहले उनको एमपी के राजधानी भोपाल स्थित बंसल अस्पताल में एडमिट कराया गया था। जिसके दो दिन बाद झा को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के मेदांता अस्पताल में लाया गया।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दें।

अगले हफ्ते बदले जाएंगे दिल्ली भर के तिरंगे, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर निर्देश जारी; हर 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राजधानी दिल्ली में तिरंगे को लेकर दो साल पहले एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की थी। मगर सरकार चाहती है कि तिरगों को लेकर अधिक सतर्कता बरती जाए। इसे देखते हुए सरकार ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश देकर और सतर्क रहने को कहा है। योजना के तहत तिरंगे का हर समय अतिरिक्त सेट तैयार रखा जाएगा।

नई दिल्ली। अगले सप्ताह दिल्ली भर के तिरंगे बदले जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सरकार ने तिरंगों के रखरखाव को लेकर फिर से निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार विभाग को हर 15 दिन में सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। किसी स्थान पर कोई तिरंगा कट-फट जाने पर कितनी देर में बदला गया, इसकी भी सरकार को पूरी जानकारी दी जाएगी। योजना के तहत 115 फीट ऊंचाई पर 480 तिरंगे लगाए गए हैं, जबकि 20 तिरंगों की ऊंचाई है 166 फीट है।

भारतीय राष्ट्रध्वज भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। दिल्ली में जगह जगह ऊंचे पोल पर लगाए गए तिरंगे रास्ता चलते लोगों को गौरवान्वित करते हैं। कई बार लोग हवा में उड़ रहे झंडे को ठहर कर भी निहारते हैं। यह झंडे किसी तरह से खराब नहीं हों और इनकी पूरी देख रेख हो, इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दो साल पहले एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की थी। मगर सरकार चाहती है कि तिरगों को लेकर अधिक सतर्कता बरती जाए। इसे देखते हुए सरकार ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश देकर और सतर्क रहने को कहा है।

हर समय तिरंगे का एक सेट तैयार रखा जाएगा

योजना के तहत तिरंगे का हर समय अतिरिक्त सेट तैयार रखा जाएगा। एक सेट लगा होगा तो इतने समय में दूसरा सेट ड्राइक्लीन कराकर तैयार कर रख लिया जाएगा। लगाए जाने के 15 दिन के अंदर इन्हें उतारकर बदला जाएगा कि जिससे कि ये मैले न दिखाई दें। इनका व्यवस्थित तरीके से रखरखाव किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्यके इलाके में तिरंगा समितियां बनाई गई हैं जो तिरंगों की निगरानी रखेंगी।

किसी तरह का नुकसान होने पर तुरंत बदला जाएगा

हवा आंधी आदि के समय तिरंगा को किसी तरह का नुकसान होने पर समितियां संबंधित अधिकारियों को अविलंब सूचित करेंगी और उसे तुरंत बदलवाएंगी। तिरंगों की उंचाई 24 फीट और लंबाई 36 फीट है। दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि तिरंगों का रखरखाव चुनौतीपूर्ण है। सबसे बड़ी चुनौती आंधी और तेज हवा से इन्हें बचाए रखने की है। विभाग तिरंगों को लेकर संवेदनशील है। इन्हें किसी तरह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

खेलने की उम्र में सर्वोच्च बलिदान, दुश्मन सेना के चार जवानों को सुलाया था मौत की नींद

परिवहन विशेष न्यूज

देश कारगिल युद्ध (कारगिल विजय दिवस) विजय की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह युद्ध हजारों फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर मई-जून 1999 में लड़ा गया। गुरुग्राम के दौलताबाद कुणी गांव के बिजेंद्र कुमार की देश के प्रति अलग ही जज्बा था। खुद के दम पर पाकिस्तानी सेना के चार जवानों को जहन्नुम में पहुंचाया था। पढ़िए इनकी वीरता की कहानी।

गुरुग्राम। दौलताबाद कुणी गांव के बिजेंद्र कुमार के अंदर देशसेवा का ऐसा जज्बा था कि स्वजन उसकी शादी को टालकर सेना में भर्ती कराने के लिए मजबूर हो गए।

उसने अपने खेलने-कूदने की उम्र को सेना के लिए समर्पित कर कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इससे पहले अपनी बटालियन के साथ मिलकर उन्होंने चोटी नंबर 5685 को पाकिस्तानी सेना से मुक्त कराने के लिए धावा बोल दिया।

चोटी पर कब्जा करने के बाद फहराया राष्ट्रध्वज

मात्र 17 वर्ष और नौ महीने की उम्र में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अग्रिम पंक्ति में रहकर अकेले ही दुश्मन सेना के चार जवानों को मौत के घाट उतार दिया। चोटी पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रध्वज फहराया। इसी दौरान एक पहाड़ी की आड़ में घात लगाए बैठे दुश्मन सेना के जवानों से बिरेंद्र को निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर दी।

एक गोली उनके सीने में लगी और वह हमेशा के लिए भारत माता की कोख में सो गए। बिजेंद्र कुमार की बचपन से ही सेना में भर्ती होकर दुश्मनों को धूल चटाने की इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने दिन-रात शारीरिक मेहनत की। उनकी इच्छा पूरी हुई और वह सेना में भर्ती हो गए। प्रशिक्षण पर जाने से पहले स्वजन से कहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा, वह दुश्मनों को निबटा देगा।

'पहले देश के लिए कुछ कर लूं, फिर शादी कर देना'

ट्रेनिंग पूरी कर 28 दिन के लिए घर आए। स्वजन ने शादी के लिए कहा तो जवाब दिया कि पहले देश के लिए कुछ कर लूं, फिर शादी कर देना। इसके बाद भी स्वजन ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी बीच कारगिल युद्ध हो गया। उन्हें भी कारगिल जाने का आदेश मिला। 13 कुमांउ रेजीमेंट में शामिल हुए।

दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल ऑप्रेशन मेघदूत और बाद में आप्रेशन विजय में भाग लिया। 30 अगस्त 1999 को वह युद्ध में मात्र 17 साल 9 महीने की उम्र में बलिदान हो गए। वह कारगिल बलिदानियों में सबसे कम उम्र के थे। बलिदानी जवान बिजेंद्र कुमार के बड़े भाई राजेंद्र कुमार का गला रुंध गया।

हर पल गर्व का अनुभव- बिजेंद्र कुमार के भाई

वह कहते हैं कि बिजेंद्र के भीतर शुरू से ही देशप्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी थी। वह हर समय देश के लिए कुछ करना चाहते थे। सेना में भर्ती होने के बाद इतने खुश थे, जैसे उन्हें जीवन में सबकुछ हासिल हो गया। अब ऐसा लगता है कि जैसे वह देश के लिए बलिदान होने के लिए धरती पर आए थे।

प्रशिक्षण से जब लौटकर आए थे तो उनकी शादी कर दी जाती। उस समय कम उम्र में खासकर जिसकी नौकरी लग जाती थी, उसकी शादी जल्द कर दी जाती थी। उन्होंने शादी से मना कर दिया था। वह उम्र में छोटे थे, लेकिन ऐसा कर गए कि समूचे देश को उन पर गर्व है।

परिवार की कई पीढ़ियों को वह गौरवान्वित कर चले गए। हर पल गर्व का अनुभव होता है। मैं बिजेंद्र कुमार का बड़ा भाई हूं, ऐसा कहने पर सीना चौड़ा हो जाता है। सरकार ने सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समाज के लोग भी पूरे परिवार को विशेष सम्मान देते हैं।

झपकी आने पर फुटपाथ पर चढ़कर पलटा ट्रक, चपेट में आकर महिला की मौत

गाजियाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में गौड़ ग्रीन एवेन्यू कट के पास बीती रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मोड़ने के दौरान झपकी आने पर अनियंत्रित होकर ट्रक फुटपाथ पर चढ़कर पलट गया। इससे फुटपाथ पर जड़ी बुटी की दुकान लगाने वाले महिला की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में गौड़ ग्रीन एवेन्यू कट के पास मोड़ने के दौरान झपकी आने पर अनियंत्रित होकर ट्रक फुटपाथ पर चढ़कर पलट गया। इससे फुटपाथ पर जड़ी बुटी की दुकान लगाने वाले महिला की चपेट में आकर मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में ले लिया है।

पुलिस के मुताबिक, 25 जुलाई की मध्यरात्रि करीब सवा दो बजे एनएच नौ से गौड़ ग्रीन एवेन्यू कट से ट्रक नीचे उतर रहा था। मोड़ पर चालक को झपकी आ गई। ट्रक फुटपाथ पर चढ़कर पलट गया।पास में ही फुटपाथ पर सो रही महिला ट्रक की चपेट में आ गई। घायल महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में मंगूपुरा जिला अमरोहा कि मीना की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आरोपी चालक गिरफ्तार

आरोपित चालक को पुलिस ने मौके से दबोच कर ट्रक को कब्जे में ले लिया। मृतका के स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यातायात निरीक्षक इंदिरापुरम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रक के चालक मोड़ते समय नींद आ जाने से अनियंत्रित होकर पलटकर फुटपाथ पर सो रही महिला को घायल कर देना है।

डूब गई BMW कार, डिक्की में भरा पानी; नए गुरुग्राम में जलभराव से गाड़ियां और ऑटो हुए खराब

हरियाणा के नए गुरुग्राम में बारिश होने से कई जगह पर भारी जलभराव हुआ है। सेक्टर 57 में जलभराव होने से एक बीएमडब्ल्यू कार भी डूब गई। कार की डिक्की में भी पानी भर गया है। पानी में बीएमडब्ल्यू कार की डूबने वाली फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं जलभराव होने से कई गाड़ियां और ऑटो भी खराब हुए।

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। नए गुरुग्राम में गुरुवार को मूसलधार वर्षा हुई, जिसके चलते मुख्य सड़कों से लेकर गलियां तक जलमग्न हो गईं। गैलेरिया रोड और सुपरमार्ट रोड रोड पर पेड़ गिर गए। मिलेनियम सिटी सेंटर क्षेत्र में एक से डेढ़ फुट तक वर्षा का पानी भर गया। उधर, नए गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हुए जलभराव में एक बीएमडब्ल्यू कार डूब गई। वहीं, बीएमडब्ल्यू की डिक्की में भी पानी भर गया है।

नौकरीपेशा लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना

बारिश होने के कारण स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वर्षा के कारण व्यापार केंद्र मार्केट के समीप एक पेड़ गिरने के कारण सर्विस लेन ही बंद हो गई। इसके कारण रास्ता बंद होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। नए गुरुग्राम के कई क्षेत्रों में जहां दो घंटे बादल खूब बरसे, वहीं पुराने शहर में वर्षा नहीं हुई। दिन में आशिंक बादल छाए रहे।

वहीं, न्यूनतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, 31 जुलाई तक वर्षा होने का अनुमान है। बुधवार को भी शहर में 17 एमएम वर्षा हुई थी, जिसके कारण दिल्ली-जयुपर हाईवे पर आठ किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था और नरसिंहपुर में हाईवे की सर्विस लेन पानी में डूब गई थी, जिसमें कई वाहन खराब हुए थे।

गाड़ियां और ऑटो खराब हुए

डीएलएफ फेज एक, दो, तीन और चार, सेक्टर 27, 28, 42, 43, सुशांत लोक, मिलेनियम सिटी सेंटर, आरडी सिटी के समीप सेक्टर 44 चौक, एमजी रोड, इफको चौक सहित आसपास के क्षेत्रों वर्षा के बाद भारी जलभराव हो गया। मिलेनियम सिटी सेंटर क्षेत्र में सिटी बसों के फ्लोर तक पानी भर गया। कई ऑटो और गाड़ियां पानी में बंद हो गए। दिन में 12 बजे के बाद सड़कों से पानी की निकासी हो पाई।

नगर निगम ने नालों की सफाई ही नहीं कराई

नए गुरुग्राम में नगर निगम के नालों की सफाई नहीं करने से बरसाती नालों में उफान आ गया। सुशांत लोक में घरों के आगे जलभराव होने से लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हुई। लोगों ने कहा कि मानसून सीजन से पहले नालों की सफाई नहीं की जाती है। बार वर्षा के मौसम में जलभराव होता है। मुख्य सड़कें जीएमडीए और आंतरिक सड़कें नगर निगम के अधीन हैं।

लाइसेंस बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, ड्राइविंग टेस्ट देने की बदल गई जगह; एक अगस्त से नियम लागू

नोएडा के उन लोगों के लिए जरूरी खबर है। जो स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन के बाद टेस्ट के लिए एआरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद एक अगस्त से यहां पर लाइसेंस नहीं बनेगा। अब इसके लिए सभी को दादरी के पास बिसाहड़ा सेंटर पर जाना होगा।

नोएडा। स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अब टेस्ट के लिए नोएडा एआरटीओ कार्यालय नहीं जाना होगा। एक अगस्त से टेस्ट के लिए आवेदकों को दादरी के बिसाहड़ा स्थित शिवम मार्वल मोटर ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा।

यहां प्रतिदिन 300 टेस्ट के लिए मुख्यालय की ओर से स्लाट प्रत्येक कार्यदिवस के लिए आवंटित होंगे। हालांकि प्रत्येक माह 3187 स्थाई लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है। एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद एक अगस्त से अब किसी भी आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय में स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य नहीं होगा।

आवेदकों को आनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए समय और तिथि का निर्धारण होगा। इसके बाद आवेदकों को एआरटीओ कार्यालय आकर टेस्ट देना होता था, अब एक अगस्त के बाद आवेदकों को स्थाई लाइसेंस के टेस्ट के लिए एआरटीओ कार्यालय नहीं आना होगा।

इसके लिए दादरी के पास बिसाहड़ा स्थित सेंटर पर जाना होगा। ऑनलाइन मिलने वाले आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य एआरटीओ कार्यालय में होगा। टेस्ट बिसाहड़ा में होगा। वहीं से टेस्ट में पास या फेल होने का नतीजा मिलेगा। टेस्ट में सफल आवेदकों के लाइसेंस लखनऊ से प्रिंट होने के बाद आवेदक के पते पर पहुंचेंगे।

कांग्रेस और खालिस्तान में गर्भनाल का रिश्ता!

राकेश सैन

देश के समक्ष अब यह रहस्य नहीं रहा कि अलगाववादी सोच के व्यक्ति जरनैल सिंह भिण्डरांवाले को पंजाब की अकाली राजनीति को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा और उस पर खालिस्तानी लेबल चस्पा किया।

माँ और सन्तान के बीच गर्भनाल का रिश्ता ही ऐसा होता है, कि प्रसव के बाद शरीर अलग होने के बावजूद भी आत्मीयता बनी रहती है। सन्तान को पीड़ा हो तो माँ बिलख उठती है। ऐसा ही गत 25 जुलाई को संसद भवन में देखने को मिला जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालन्धर से कांग्रेस के सांसद चरनजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल के पक्ष में आह भरी। चन्नी के शब्दों में 20 लाख लोगों के खडूर साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि अमृतपाल को जेल में रखा जा रहा है, यह भी एमरजेंसी है। ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में डिब्रूगढ़ जेल में नजरबन्द खालिस्तान प्रचारक व अजनाला कोतवाली हिंसा का मुख्य आरोपी अमृतपाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता है और कांग्रेस सांसद चन्नी लोकसभा में उसके ही पक्ष में बोल रहे थे। रोचक बात तो ये है कि अमृतपाल को जेल में भेजने वाली पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सांसद भी सुन्न अवस्था में चन्नी के साथ वाली सीटों पर ही बैठे थे।

वैसे चन्नी के बौद्धिक व प्रशासनिक योग्यता के स्तर का इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी, 2018 में कैप्टन अमरिन्द्र सिंह की सरकार के तकनीकी शिक्षा मन्त्री रहते हुए उन्होंने प्राध्यापकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि क्रिकेट की तरह टॉस करके की थी। उस समय देश-दुनिया में इस घटना को बड़े हास्यस्पद अन्दाज में कहा और सुना गया था। बाद में मुख्यमन्त्री बनने के बाद चन्नी प्रधानमन्त्री की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पाए और बठिण्डा से फिरोजपुर जाते हुए कथित किसान आन्दोलनकारियों ने प्रधानमन्त्री के काफिले को घेर लिया था। इस पर चन्नी ने सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर डालने का प्रयास किया। केवल इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों के समय जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को चन्नी ने भाजपा की रणनीति बताया था। अब चन्नी द्वारा किसी खालिस्तानी का समर्थन करना चाहे किसी को चौंकाता हो परन्तु 1980 के दशक की राजनीतिक कलाबाजियां देख चुकी पीढ़ी अच्छी तरह जानती है कि चन्नी का अमृतपाल के प्रति दुःख अनायास नहीं बल्कि यह कांग्रेस और खालिस्तान के बीच गर्भनाल के रिश्ते की टीस है।

देश के समक्ष अब यह रहस्य नहीं रहा कि अलगाववादी सोच के व्यक्ति जरनैल सिंह भिण्डरांवाले को पंजाब की अकाली राजनीति को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा और उस पर खालिस्तानी लेबल चस्पा किया। रिसर्च एण्ड एनालाइसेज विंग (रॉ) के सेवानिवृत अधिकारी जी.बी.एस. सिद्धू अपनी पुस्तक 'खालिस्तान षड्यन्त्र की इनसाइड स्टोरी' में दावा करते हैं कि जब भी भिण्डरांवाले से कोई संवाददाता खालिस्तान की मांग के बारे पूछते तो उसका यही जवाब होता था कि- हम खालिस्तान की मांग नहीं करते पर सरकार इसका प्रस्ताव करती है तो हम इन्कार भी नहीं करेंगे।'

चूंकि पंजाब के नर्म दलीय अकाली नेताओं को कमजोर करने के लिए गर्मदलीय लोगों के साथ खालिस्तान का लेबल चस्पा करना जरूरी था, तो 13 अप्रैल, 1978 में हुए निरंकारी-सिख टकराव की घटना के बाद ऐसी शक्ति का खड़ा करना जरूरी हो गया जो खुल कर खालिस्तान की बात करे। चूंकि भिण्डरांवाला न तो खालिस्तान की मांग करने वाला था और न ही विरोध, तो उसके साथ इस बिखराव की मांग को आसानी से जोड़ा जा सकता था। उस समय कांग्रेस नेताओं ने यह काम बड़ी बाखूबी किया।

उस समय भारत में काम कर रहे बीबीसी लन्दन के पत्रकार मार्क टुल्ली व सतीश जैकब की पुस्तक 'अमृतसर- मिसेज गान्धी लास्ट बैटल' के पृष्ठ 60 पर दावा करते हैं कि 'इस काम के लिए पंजाब में दल खालसा के नाम से कट्टरवादी संगठन का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक चण्डीगढ़ के अरोमा होटल में हुई जिसका 600 रुपये का भुगतान ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया।'

पत्रकार कुलदीप नैयर की पुस्तक 'बियाण्ड द लाइन्स -एन ऑटोबायोग्राफी' के अनुसार, 'इस संगठन के उद्घाटन समारोह में सिख पन्थ की अवधारणा और उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को जीवित रखने का संकल्प लिया गया। संगठन का राजनीतिक उद्देश्य खालसा का बोलबाला बताया गया।'

एक अन्य पत्रकार जीएस चावला अपनी पुस्तक 'ब्लडशेड इन पंजाब- अनटोल्ड सागा ऑफ डिसीट एण्ड सैबोटेज' में लिखते हैं कि- 'दल खालसा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने पहले चण्डीगढ़ में एक पूर्व कांग्रेसी सांसद के यहां स्टेनोग्राफर की नौकरी की थी। 6 अगस्त, 1978 को चण्डीगढ़ के सेक्टर 35 में स्थित गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में यह घोषणा की गई कि दल खालसा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्र सिख साम्राज्य की स्थापना सुनिश्चित करना है। अगले दिन पंजाब के कई समाचारपत्रों में यह खबर छपी, प्रेस कान्फ्रेंस का खर्चा भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं ने उठाया।'

देश के सुविख्यात विचारक कुप्पहल्ली सीतारामैया सुदर्शन अपनी पुस्तक 'यों भटका पंजाब' में लिखते हैं कि-'कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ने भी पंजाब समस्या को उग्र बनाने में बहुत मदद दी है। केवल दलीय दृष्टिकोण से ही समस्याओं को देखने का उसका स्वभाव रहा है, इसलिए सत्ताहीन अवस्था में अकाली दल को शह देने के लिए उसने भिण्डरावाले को उभारा। कांग्रेस की आपसी धड़ेबन्दी ने भिण्डरावाले की उग्रता के विरुद्ध समय रहते कड़े कदम उठाने नहीं दिये और जब भिण्डरावाले ने भस्मासुर का रूप लेकर अपने वरदाता को ही भस्म करने के लिए हाथ बढ़ाया तब कांग्रेसी शासन को ऐसी कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ा जिसने समाज में अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया तथा उग्रपन्थियों को खुलकर खेलने का मौका दे दिया।'

देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर काडर तक किस तरह दिशाभ्रम के शिकार हैं इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि पार्टी एक तरफ तो श्रीमती इन्दिरा गान्धी, श्री राजीव गान्धी व स. बेअन्त सिंह को आतंकियों के हाथों मिली शहादत की विरासत अपना बताती है तो दूसरी ओर अमृतपाल जैसों के दुःख में पतली होती रही है। और अधिक विस्मयकारी बात तो यह है कि चन्नी को वहां बैठे किसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने ऐसा करने से रोका तक नहीं और न ही बाद में खेद जताया गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में खालिस्तानी अलगाववाद व आतंकवाद की आग दबी जरूर है परन्तु पूरी तरह बुझी नहीं। इसका साक्षात उदाहरण है कि कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में खालिस्तानियों की खुराफात दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इन देशों में हिन्दू समाज, मन्दिरों व संस्थानों पर हमले, सोशल मीडिया पर विषैला प्रचार निरन्तर जारी है। ऐसे में खालिस्तानी आतंकवाद को देश की संसद में समर्थन मिलता है तो यह गलती भिण्डरांवाले के पुनर्जीवन सरीखी होगी।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ने पकड़ी रफ्तार, फेम 2 योजना के तहत 8 लाख से ज्यादा बिके ई-वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

भारत सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल रंग ला रही है। 21 जुलाई, 2023 तक भारत में फेम 2 योजना के तहत 8 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा चुके हैं। 2019 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य सार्वजनिक और साझा परिवहनों के विद्युतीकरण करना था।

भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना के चरण 1 के तहत 520 चार्जिंग स्टेशन और चरण 2 के तहत 2,877 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त 7,432 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार ने ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए और भी कदम उठाए हैं, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना, ईवी को परमिट आवश्यकताओं से छूट देना और रोड टैक्स माफ करना जैसे पहल शामिल है। इसको बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता पहल की गई है तथा ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन और वेबिनार आयोजित किए गए हैं।

फेम 2 योजना के तहत 7,40,722 ई-2 पहिया वाहन, 83,420 ई-3 पहिया वाहन, 8,982 ई-4पहिया वाहन कुल मिलाकर 8 लाख 32 हजार 824 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गये हैं। इस तरह देखें तो सरकार के प्रयासों का उद्देश्य भारत को वैश्विक ईवी बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है।

सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपायों की घोषणा की

परिवहन विशेष न्यूज

हाल ही में राज्य सभा सत्र में इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने स्पष्ट किया कि फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। इसके बजाय, यह योजना उपभोक्ताओं के लाभ पर केंद्रित है।

2019 में 10,000 करोड़ रुपये के शुरुआती बजट के साथ शुरू की गई और बाद में 1,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट के साथ फेम II योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना है। 30 मार्च, 2024 तक, इस योजना ने 15.4 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी है, जिसमें लगभग 13.6 मिलियन दोपहिया, 1.57 मिलियन तिपहिया और 20,352 चार पहिया वाहन शामिल हैं।

फेम 2 योजना के उल्लेखनीय लाभार्थियों में इलेक्ट्रिक श्री और फोर-व्हीलर्स के लिए टाटा मोटर्स और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए ओला शामिल हैं। कुल मिलाकर इस पहल के तहत 221 इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों को समर्थन मिला है।

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मोटर वाहन बाजार के रूप में भारत पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन से अधिक टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सरकार का अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहन मोटर वाहन क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण खंड बन जाएगा।

ईवी उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने 15 मार्च 2024 को 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' शुरू की। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक ईवी निर्माताओं को आकर्षित करना और भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

अनुमोदित निर्माता पांच वर्षों के लिए 15% की कम सीमा शुल्क पर इलेक्ट्रिक यात्री कारों का आयात कर सकते हैं, जो वर्तमान 70-100% से कम है।

इस नई योजना के लिए पहला हितधारक परामर्श 18 अप्रैल 2024 को हुआ, जिसमें प्रमुख मूल उपकरण निर्माता यानी ओईएम उपस्थित थे।

यह योजना भारत की ईवी अपनाने और विनिर्माण में तेजी लाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह फेम इंडिया योजना, ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाओं और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी एसीसी विनिर्माण जैसी मौजूदा पहलों का पूरक है।

भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी ने कहा, ₹यह योजना वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगी। इससे रोजगार भी पैदा होगा और 'मेक इन इंडिया' का लक्ष्य भी हासिल होगा।₹

सरकार का अनुमान है कि 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन 35-40% दोपहिया वाहनों, 9-11% निजी चार पहिया वाहनों तथा 20-25% साझा चार पहिया वाहनों का हिस्सा बन जाएंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का यह व्यापक दृष्टिकोण स्वच्छ, अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस पहल से वायु प्रदूषण में कमी, व्यापार घाटे में सुधार, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता में कमी और देश में नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने सहित कई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने की उम्मीद है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना को दो महीने के लिए बढ़ाया

परिवहन विशेष न्यूज

भारी उद्योग मंत्रालय ने अस्थायी इलेक्ट्रिक वाहन योजना को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी ईएमपीएस 1 अप्रैल 2024 को 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी।

मार्च में फेम 2 योजना की समाप्ति के बाद ईएमपीएस को शुरू में केवल चार महीनों के लिए योजनाबद्ध किया गया था, क्योंकि नई फेम योजना की घोषणा चुनावों के बाद ही की जा सकती थी। सूत्र संकेत देते हैं कि विस्तारित ईएमपीएस में अतिरिक्त दो महीनों के लिए 274 करोड़ का परिव्यय होगा। ईएमपीएस के नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं, केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। केंद्रीय बजट से पहले, मोटर वाहन उद्योग ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन प्रोत्साहन पर स्पष्टता मांगी थी, कई निर्माताओं ने अगले पांच वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निरंतर सब्सिडी का अनुरोध किया था। जबकि सरकार ने फेम 3 के लिए ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों ने मीडिया को बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक ट्रकों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिक प्रोत्साहन और फंडिंग प्रदान करने की इच्छुक है। अधिकारियों का यह भी मानना है कि अगले दो से तीन वर्षों में दो और तीन पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं ने नई योजना में ई-कारों को शामिल करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

टाटा पावर सोलर और बैंक ऑफ इंडिया ने ईवी चार्जिंग फाइनेंस के लिए मिलाया

परिवहन विशेष न्यूज

बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में, टाटा पावर सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशनों और रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए सस्ते वित्तपोषण विकल्प प्रदान करेगा। यह साझेदारी छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों में मदद करती है , जो पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवासीय उपयोगकर्ताओं, हाउसिंग सोसाइटियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित विविध प्रकार के ग्राहकों को लक्षित करती है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत, 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम लगाने के इच्छुक आवासीय ग्राहक केवल 5% मार्जिन मनी की आवश्यकता के साथ 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन 7.10% प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर पर दिए जाते हैं, ये लोन बिना किसी जमानत के दिए जाते हैं और इनकी अवधि 10 साल तक होती है। 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट तक की स्थापना के लिए, 5% मार्जिन मनी की आवश्यकता के साथ 6 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। इन लोन की ब्याज दरें 8.3% से 10.25% प्रति वर्ष तक होती हैं और ये लोन बिना किसी जमानत के भी दिए जाते हैं और इनकी अवधि 10 साल तक होती है। पंजीकृत हाउसिंग सोसाइटी और आवासीय कल्याण संघ 10% मार्जिन मनी की आवश्यकता के साथ 1 करोड़ रुपये तक के लोन का लाभ उठा सकते हैं।

सभी उद्यम पंजीकृत एमएसएमई ग्राहक जो रूफटॉप सोलर सिस्टम या ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं, वे 30 करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इन ऋणों की ब्याज दरें 9.35% प्रति वर्ष से शुरू होंगी, जिसमें 15% मार्जिन की आवश्यकता होगी और संपार्श्विक-मुक्त विकल्प प्रदान किए जाएंगे। उधारकर्ता 120 महीने तक की उच्च पुनर्भुगतान अवधि का लाभ उठा सकते हैं। ऋण पेशकश के तहत MSE-GIFT (ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन) ब्याज छूट का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक दीपेश नंदा ने कहा, ₹हमें विभिन्न ग्राहक खंडों में स्थायी ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहयोग करने पर गर्व है। यह साझेदारी लाखों लोगों तक सस्ती, स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने और भारत के कम कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलाव को गति देने के हमारे मिशन के अनुरूप है। बैंक ऑफ इंडिया जैसे भागीदारों की मदद से, हम रूफटॉप सोलर या ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के इच्छुक अपने ग्राहकों के लिए किफायती और आसान वित्तपोषण समाधान प्रदान करने में प्रसन्न हैं, जो उन्हें अपनी हरित ऊर्जा यात्रा पर अपना पहला कदम उठाने में मदद करेगा।"

ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) के साथ भविष्य में करें निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एफओएफ हाल ही में ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया एक नया फंड ऑफ फंड्स है। यह फंड निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और संबंधित प्रौद्योगिकियों में शामिल कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है।

फंड ऑफ फंड्स (FoF) एक म्यूचुअल फंड है जो सीधे स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करने के बजाय अन्य म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव फंड ऑफ फंड्स विशेष रूप से निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव सूचकांकों को लक्षित करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, घटकों, कच्चे माल और प्रौद्योगिकी के उत्पादन और आपूर्ति में शामिल प्रमुख भारतीय कंपनियां शामिल हैं।

निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स एक बेंचमार्क है जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इंडेक्स में वे स्टॉक शामिल हैं जो निफ्टी 500 का हिस्सा हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, घटकों और संबंधित प्रौद्योगिकियों के निर्माण में लगे हुए हैं। इंडेक्स की आधार तिथि 2 अप्रैल, 2018 है और इसका आधार मूल्य 1000 है। विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए, विनिर्माण समूह में स्टॉक का भार 40% पर सीमित है, जबकि व्यक्तिगत स्टॉक का भार 8% पर सीमित है। इंडेक्स को अर्ध-वार्षिक रूप से पुनर्गठित किया जाता है और इसे प्रासंगिक और अद्यतित रखने के लिए तिमाही में पुनर्संतुलित किया जाता है।

भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार कई कारकों के कारण तेजी से विकास कर रहा है। अगले दशक में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। भारत सरकार ने ईवी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई नीतियां शुरू की हैं, जिनमें ईवी खरीद के लिए सब्सिडी, कर प्रोत्साहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश शामिल हैं। इससे ईवी क्षेत्र के विकास में और तेजी आएगी। ये कारक ईवी उद्योग में शामिल कंपनियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, जिससे यह एक आकर्षक निवेश अवसर बन जाता है।

ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एफओएफ वर्तमान में न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) के रूप में लाइव हैं। यह निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर है, क्योंकि यह उन्हें भारतीय ईवी क्षेत्र में शामिल कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने का मौका देता है, व्यक्तिगत स्टॉक्स चुनने की आवश्यकता के बिना। एनएफओ अवधि अस्थायी रूप से 24 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है, जिससे निवेशकों को इस अनूठे अवसर का लाभ उठाने के लिए सीमित समय मिल रहा है।

किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना उचित है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना जोखिम भरा है और इन जोखिमों और लाभों को पूरी तरह से समझना महत्वपूर्ण है। निवेशकों को योजना की जानकारी के दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ना चाहिए और अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर विचार करना चाहिए। एनएफओ सभी प्रमुख म्यूचुअल फंड निवेश प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है, जिससे निवेशकों के लिए इसमें भाग लेना आसान हो जाता है।

ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एफओएफ उन लोगों के लिए एक प्रभावी निवेश अवसर प्रस्तुत करता है जो भारत के ईवी क्षेत्र के विकास पर पूंजी लगाना चाहते हैं। अग्रणी कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो और सरकारी पहलों से समर्थन के साथ, यह फंड इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के तेजी से विस्तार से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इस अभिनव निवेश विकल्प पर विचार करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें कि क्या यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुकूल है। प्रमुख म्यूचुअल फंड प्लेटफ़ॉर्म पर ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एफओएफ देखें या व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करें।

ग्रो म्यूचुअल फंड की नवीनतम पेशकश के साथ आज ही परिवहन के भविष्य में निवेश करें और भारत की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की लहर पर सवार हों।

Be.EV ने ईवी नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए Paua के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर Be.EV ने Paua के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वाणिज्यिक चालकों की पहुंच में 700 से अधिक चार्ज प्वाइंट आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ग्रेटर मैनचेस्टर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन संचालित करने वाले व्यवसायों के पास अब चार्जिंग कवरेज में काफी सुधार हुआ है।

Be.EV के जुड़ने से ग्रेटर मैनचेस्टर क्षेत्र में Paua के ग्राहकों को 1,800 EV कनेक्टर तक पहुंच प्राप्त होगी। इनमें से 1,000 से अधिक उच्च-शक्ति वाले DC चार्जर (50kW या उससे अधिक) हैं। इससे ड्राइवरों को हर वर्ग मील में कम से कम दो चार्ज पॉइंट कनेक्शन मिलते हैं।

Be.EV उत्तरी इंग्लैंड और उसके बाहर चार्जिंग पॉइंट कवरेज बढ़ाने के मिशन पर है। इस नेटवर्क पर इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को Be.EV के राष्ट्रीय विस्तार से भी लाभ होगा, जिसमें 2025 के अंत तक कुल 1,100 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएँगे।

ऑक्टोपस एनर्जी जेनरेशन द्वारा समर्थित कंपनी के पास 700 लाइव चार्जिंग पॉइंट हैं और 2024 के अंत तक पूरे यूके में 300+ अतिरिक्त चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं।

Be.EV नेटवर्क पर सभी ईवी चार्जिंग ऑक्टोपस एनर्जी से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 100% समर्थित है।

Paua अब ड्राइवरों को 17,000 से अधिक स्थानों पर 54,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें पूरे यूके में 35 से अधिक चार्जिंग प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यूके के सभी क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज में वृद्धि से ड्राइवरों का इलेक्ट्रिक वाहनों पर जाने का डर कम हो जाता है, जिससे व्यवसायों के लिए अपने परिवहन उत्सर्जन को कम करना आसान हो जाता है।

Paua ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिससे अनेक नेटवर्कों के सभी डेटा को एक केंद्रीयकृत स्थान पर लाना तथा एक मासिक बिल तैयार करना आसान हो गया है।

ड्राइवर बस चार्जर खोजते हैं (कभी भी 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं) फिर चार्ज करने के लिए Paua कार्ड पर टैप करें और फिर से सड़क पर निकल पड़ें। प्रबंधकों को अपने सभी चार्जिंग डेटा एक ही जगह पर और एक ही बिल पर उपलब्ध होते हैं, जिससे उनका अनुभव सरल हो जाता है।

Paua में अब कम से कम हर 15 मील पर एक पार्टनर कनेक्टर है। उल्लेखनीय रूप से ग्रामीण क्षेत्र कम कवर किए गए हैं, कैथनेस, नॉर्थम्बरलैंड नेशनल पार्क और नॉर्थ यॉर्कशायर मूर में चार्जर्स का घनत्व सबसे कम है।

अहमानी ईवी भारत में बैटरी विनिर्माण संयंत्र की बना रही योजना, प्रौद्योगिकी साझेदारी की संभावना को कर रही तलाश

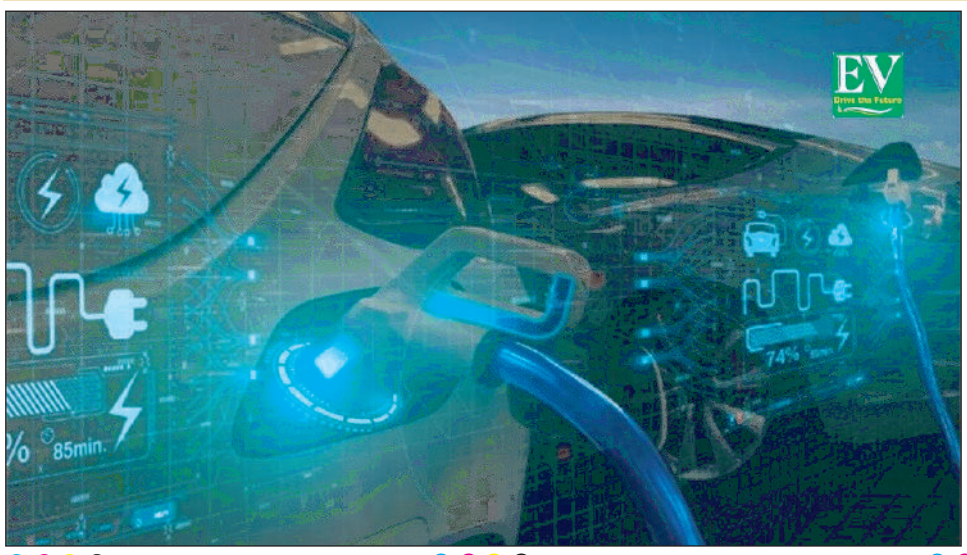

परिवहन विशेष न्यूज

ताइवान की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और AIoT स्मार्ट मोबिलिटी की अग्रणी कंपनी अहमानी EV टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बड़ा निवेश करने जा रही है।

कंपनी ने देश में मेगावाट-स्केल बैटरी प्लांट स्थापित करने की योजना की घोषणा की है और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की दिग्गज कंपनियों के साथ रणनीतिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण साझेदारी को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। कंपनी पहले से ही 3-4 प्रमुख ईवी खिलाड़ियों के साथ उन्नत स्तर की चर्चा कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार के दो दशकों से अधिक के अनुभव पर आधारित मजबूत नींव के साथ, अहमानी बैटरी प्रौद्योगिकी, मोटर सिस्टम और बुद्धिमान बेड़े प्रबंधन समाधानों में विशेषज्ञता का खजाना लेकर आई है। कंपनी का URDA AIoT मोबिलिटी सिस्टम, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेड़े के प्रबंधन के लिए एक अग्रणी प्लेटफ़ॉर्म है, जिसने अपनी दक्षता और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।

सहायक सरकारी नीतियों और टिकाऊ परिवहन के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर भारत का महत्वाकांक्षी कदम अहमानी के लिए एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करता है। स्थानीय बैटरी विनिर्माण सुविधा स्थापित करके, कंपनी का लक्ष्य ईवी मूल्य श्रृंखला में भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान देना है, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करना और घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा अहमानी द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण साझेदारी की संभावना तलाशने का निर्णय भारतीय उद्योग जगत के नेताओं के साथ दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण ज्ञान, संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होगा, जिससे भारतीय बाजार के अनुरूप उन्नत इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी आएगी।

अहमानी ईवी टेक्नोलॉजी की संस्थापक और सीईओ त्जु ची कुंग ने भारतीय बाजार के बारे में अपनी उत्तेजना व्यक्त करते हुए कहा, ₹हम पिछले पांच वर्षों से भारतीय ईवी बाजार का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और इसकी अपार संभावनाओं को पहचानते हैं। हमारी मजबूत आरएंडडी क्षमताएं और सफल ट्रैक रिकॉर्ड हमें भारतीय भागीदारों के साथ सहयोग करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं।"

जैसे-जैसे भारत एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहा है, अहमानी की रणनीतिक पहल देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बैटरी विनिर्माण में कंपनी का निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी के प्रति उसका खुलापन भारत की विकास गति में उसके विश्वास और देश के विद्युतीकरण लक्ष्यों में योगदान देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गुरु का महत्व

विजय गर्ग

नए दिन नए मुद्दों और चीजों का सामना कर सकते हैं। अतः अनुभव का कोई प्रतिस्थापन नहीं है। उनके जीवन के अनुभव से आप नई चीजें सीख सकते हैं जिनका आपने अभी तक सामना नहीं किया है और हर स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ते रहने के लिए सीखते रहना होगा और यह तभी संभव है जब आपके जीवन में सही शिक्षक हों, जो आपको सिखाएंगे और जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करेंगे।

एक गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने मूल्यवान अनुभव और आशावादी विश्वासों से आपका मार्गदर्शन करता है। मेंटर हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है और आपका मार्गदर्शन करता है क्योंकि उसके पास विशेषज्ञता के कुछ क्षेत्र होते हैं जिसके आधार पर वह आपको अच्छी राय प्रदान करता है। मेंटर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए अपना समय और विशेषज्ञता खर्च करता है जिसे उसकी सहायता या सलाह की आवश्यकता होती है। करियर और व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य से मेंटर और मेंटर के बीच के संबंध को मेंटरशिप कहा जाता है। यह एक औपचारिक रिश्ता हो सकता है या अनौपचारिक रिश्ता गुरु और शिष्य के बीच संबंधों पर निर्भर करता है। एक गुरु आपके शिक्षक, कोच, शिक्षक, माता-पिता, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास कुछ अनुभव हो और जो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। सलाहकार अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो कम अनुभवी लोगों की बेहतरी के लिए उनके साथ अपने मूल्यवान विचार और सीख साझा करने के लिए, तैयार रहते हैं। यह संपूर्ण मेंटरशिप अवधारणा कई व्यक्तियों के लिए बहुत मूल्यवान है जिन्हें वास्तव में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की सफलता में मेंटरशिप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरों की मदद या मूल्यवान सलाह के बिना एक महान स्थान हासिल नहीं कर सकता है। हमारे पास अपनी निजी जिंदगी और पेशेवर जिंदगी में आने वाली सभी समस्याओं और कठिनाइयों का कोई संभावित समाधान नहीं है, हमें खुद का कूटनीतिक बनाने के लिए बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में गुरु का महत्व गुरु हमारे जीवन में विभिन्न भूमिकाएँ निभाता है और विभिन्न परिस्थितियों में हमारा समर्थन करता है। हमारे जीवन में एक अच्छा गुरु होने के अनेक लाभ हैं। एक अच्छा गुरु होने के कुछ मुख्य लाभों पर आगामी बिंदुओं में चर्चा की जाएगी। समर्थनः यह सलाहकारों की मुख्य भूमिकाओं में से एक है। वे हमारे बुरे समय और बुरे मूड में हमारा साथ देते हैं। जब हम अपने जीवन में असफलता का सामना करेंगे तो वे हमें प्रेरित करेंगे और असफलता से उबरने और जीवन में आगे अच्छा करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे आपकी समस्याओं को सुनते हैं और आपको अपने जीवन का सबसे अच्छा पक्ष दिखाते हैं, भले ही आप बुरे समय में हों। अधिकतर, जब युवा लोग अपना करियर बना रहे होते हैं तो उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है, उस समय एक अच्छे गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस समय युवाओं को अपनी विफलता से उबरने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करने के लिए सही प्रेरणा की आवश्यकता होती है। चूंकि असफलता मन की निराशाजनक स्थिति की ओर ले जाती है, उस समय मूल्यवान अनुभव वाला व्यक्ति आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है क्योंकि वे पहले से ही अपने अतीत में इसी स्थिति का सामना कर चुके हैं और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय क्या करना है। उनके विचार और राय आपको अपने जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। अनुभवः आपको पीछे एक अच्छा गुरु होने का एक और गुण मूल्यवान अनुभव प्राप्त करना है जो आपको किताबों में नहीं मिल सकता है। चूंकि सलाहकार पहले से ही अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, वे हर बाधा को जानते हैं और साथ ही इन बाधाओं से निपटने की रणनीति भी जानते हैं। आप उनसे भविष्य में अपना करियर बनाते समय या निजी जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में विचार प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि अनुभव बहुत महंगी चीज़ है, इसलिए जीवन का अनुभव पाने के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है; आप हर नए दिन नए मुद्दों और चीजों का सामना कर सकते हैं। अतः अनुभव का कोई प्रतिस्थापन नहीं है। उनके जीवन के अनुभव से आप नई चीजें सीख सकते हैं जिनका आपने अभी तक सामना नहीं किया है और हर स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ते रहने के लिए सीखते रहना होगा और यह तभी संभव है जब आपके जीवन में सही शिक्षक हों, जो आपको सिखाएंगे और जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप दूसरों के अनुभवों को सुनकर और उनसे सीखकर खुद को गलतियाँ करने से बचा सकते हैं ये गलतियाँ उनके जीवन में पहले से ही हैं। गुरु ने जीवन के उस पथ को कवर किया जिस पर शिष्य वर्तमान में यात्रा कर रहा है, इसलिए जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक गुरु आपका पूरे समय मार्गदर्शन कर सकता है। नजरियाः चीजों और परिस्थितियों को देखने का आपका नजरिया हर व्यक्ति से अलग होता है। धारणा और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। आप वास्तविकता से भिन्न चीजें देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समान स्थितियों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करता है। तो, आप अपने गुरु के साथ स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं और वह आपको उस स्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो उसके बाद आपके पास विकल्प हो सकता है। एक ही समस्या पर आपकी कम से कम दो अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं; आप आसानी से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर सकते हैं। कमजोरियाँः एक सच्चा गुरु हमेशा आपकी दर्पण छवि को उजागर करेगा। वह आपसे झूठ बोलने के बजाय सच बताता है कि आपने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। वह निश्चित रूप से आपकी कमजोरियों और ताकतों को जानता है। और हमेशा आपकी बुरी चीजों को दूर करने और आपके कमजोर हिस्से को काटने में आपकी मदद करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन अगर वहां कोई ऐसा मौजूद है जो हमें समझता है और हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है। तब निश्चित रूप से हम अपनी खामियों पर काम करेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। इसमें एक अच्छा गुरु हमेशा हमारी मदद करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और खुद को आदर्श बना सकते हैं। किसी को उनकी गलतियों और खामियों का एहसास कराना सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है लेकिन एक अच्छा शिक्षक जानता है कि इसे कैसे करना है और इसे सही तरीके से कैसे पूरा करना है। एक सलाहकार इस प्रक्रिया में एक सलाहकार के साथ-साथ एक मित्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाएगा, एक मित्र जो आपकी खामियों को जानता है और एक सलाहकार जो आपको इसे सही करने में मदद करता है। वे आपको बेहतर समझते हैं और आपकी पिछली गलतियों को स्वीकार करते हैं और आपके आने वाले समय में आपको एक अच्छा और सफल इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। अपना कम्फर्ट जोन तोड़ेंः एक अच्छा गुरु हमेशा आपको आपके कम्फर्ट लेवल से बाहर कर देता है। आपके आस-पास आपके आराम क्षेत्र में हमेशा कुछ लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन एक वफादार गुरु हमेशा आपको सुधार करने और अपने आराम को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है ताकि आप नए अनुभव प्राप्त कर सकें। एक आत्मविश्वासी गुरु आपको हमेशा नई दिशाएँ और विकल्प देता है, साथ ही जब आप खुद को अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकालते हैं तो वह आपका समर्थन भी करता है। इस नए गठन के लिए गुरु और शिष्य के बीच विश्वास और प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुरु हमेशा आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है और आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे पाने में मदद करता है। अपने इच्छित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा है। हम सभी के जीवन में निश्चित रूप से लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं लेकिन हम उन्हें तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू नहीं करते। आत्मविश्वास बनाएँः आपके जीवन में महान गुरु होने से आत्मविश्वास का स्तर बहुत अच्छा होता है। जब हम जानते हैं कि कोई हमारी तरफ देख रहा है और हमारे बुरे समय में हमारी मदद कर रहा है तो हम बहुत आश्वस्त महसूस करते हैं और उत्साहपूर्वक अपना काम करते हैं। गुरु हमें इस तरह प्रोत्साहित करते हैं कि हमें यह महसूस होने लगता है कि हम काम कर सकते हैं और हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। सलाहकार हमारी क्षमताओं को देख सकते हैं जो हम अपने आप में नहीं देख सकते क्योंकि हम अक्सर अपने आप को और हमारे पास मौजूद क्षमताओं को कम आंकते हैं। लेकिन गुरु हमें हमारे भीतर मौजूद कौशल से अवगत कराते हैं और हम अपने बारे में आश्वस्त महसूस करने लगते हैं। आत्मविश्वास मुख्य चीज़ों में से एक है जो हमें वह चीज़ हासिल करने में मदद करता है जो हम चाहते हैं। आत्मविश्वास हमारी इच्छाशक्ति को मजबूत करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप सोचते हैं कि आप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो आपको कुछ अच्छे गुरु खोजने चाहिए ताकि आप जो हासिल कर सकें वह हासिल कर सकें।आप चाहते थे. गुरु अनमोल रत्नों की तरह होते हैं जो बिना किसी लालच के हमेशा हमें चमकाते रहते हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आपके विचारों को गति देते हैं, आपके खाली समय में भी सीखते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और अपने मूल्यवान अनुभवों से सीख भी देते हैं। आपके पास विभिन्न कौशल हो सकते हैं लेकिन इन कौशलों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उपयोग करने के लिए आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो बताता है कि अपना बेहतर उपयोग कैसे करें। उपर्युक्त कारणों से, हमें पता चलता है कि सलाहकार विभिन्न कारणों से अमूल्य हैं और वे हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक शीर्ष श्रेणी के व्यंजन की गुप्त सामग्री की तरह हैं। अपने अच्छे समय में अपने गुरुओं को न भूलें क्योंकि बुरे समय में वे आपके साथ होते हैं। वे आपको सफलता का मानचित्र प्रदान करते हैं और सफलता की राह भी दिखाते हैं। वे आपको वे आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं जिनकी सफलता की ओर यात्रा में आवश्यकता होती है। आपके गुरुओं द्वारा आपको प्रदान की गई सभी प्रेरणा और प्रेरणा के परिणामस्वरूप एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण होता है। इसलिए, हमेशा अपने गुरुओं के साथ रहें और उनका एहसान मानें क्योंकि वे ही आपके सफल जीवन के निर्माता हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

संपादक की कलम से

मीठी गोलियां या कड़वे घूंट

छोटे बजट की बड़ी कहानी लिखते-लिखते हिमाचल अपने ही वित्तीय ध्रुव में फंस गया है। न बही-खाते सही और न ही कमाई के स्रोत अव्वल। वह दौर बदल गया जब राज्य की मदद में केंद्र का प्रश्रय पुरस्कार था, उपहार था। अब राज्य के सारे मानक राजनीति की मुट्ठी में बंद है और नेताओं की अचकनें गर्दन में फंसी हैं। नेताओं में विजन नहीं और व्यावहारिक सियासत में राज्य के प्रति सरोकार नहीं। अहंकार में लिप्त राजनीति को केवल सत्ता सुख चाहिए और सत्ता को अपनों का मोह चाहिए। बहरहाल राजनीति और राजनीतिक संगठनों के अदब और हैं, जबकि सरकारों के पांव में उधार की मेहंदी लगाकर भी वित्तीय बाधाओं के कांटे दूर नहीं होते। बेशक इससे पहले भी सरकारों ने संसाधन बढ़ाने के लिए कुछ रास्ते चुने, कुछ बैठकें कीं और कुछ निष्कर्षों की सीमा रेखा पर हिम्मत भी दिखाई, लेकिन चुनाव के भूत ने हमेशा ऐसी मंशा को डराया-धमकाया और अंत में वही 'ढाक के तीन पात' बन कर रह गया सारा प्रयास, सारी हिम्मत। अब पुनः व्यवस्था परिवर्तन के जोरदार नारे पर आई सुक्खू सरकार, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के मुहाने पर अपने लिए नए आर्थिक दस्तखत खोज रही है। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में चंद्र कुमार, हर्षवर्धन, राजेश धर्माणी और योजना सलाहकार डा. बासु सूद बैठे तो दिक्कतों के नजराने पेश हुए, यानी राज्य की औकात तो अपने दम पर सरकारी कर्मचारियों को खिलाने-पिलाने की भी नहीं है, फिर भी अब तक मंत्रिमंडलीय फैसलों का यही पक्ष सब पर भारी है। आर्थिक परिदृश्य में अपनी आय को पूरी तरह निचोड़कर भी हिमाचल अगर 12629 करोड़ कमा रहा है, तो केवल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही इसे 16000 करोड़ के करीब चाहिए। इस पर कई तरह के एरियर, घटती केंद्रीय रियायतें, घाटा अनुदान और बंद होते जीएसटी मुआवजे ने वित्तीय प्रबंधन के एक साथ कई तार तोड़ दिए हैं।

आते ही सुक्खू सरकार ने पांच-छह सौ संस्थान डिनोटिफाई किए, तो वास्तविक हिमाचल में राहत की हवाएं चलीं, मगर जब चुनाव की घंटियां बार-बार बजीं, तो यह मुहिम थक गई। ऐसे में संसाधनों की तलाशी, उनकी खोज और वित्तीय जरूरतों का गुण-दोष तब समझ आएगा, जब मीठी गोलियों की जगह कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन अगर फैसलों के इरादे में सुदृढ़ होता है, तो कोई कारण नहीं कि सबसे पहले सरकार का आकार व फिजूलखर्चियों का आधार कम किया जा सकता है। मितव्ययिता के सिद्धांत पर कभी शांता कुमार सरकार ने सरकारी आयोजनों में खानपान के नाम पर भारी-भरकम खर्चे को चाय-बिस्कुट में समेट दिया था, तो धूमल सरकार ने सरकारी वाहनों को एक दिन आराम तथा अधिकारियों को निजी वाहनों के इस्तेमाल का रास्ता दिखाया था, लेकिन सरकारों की शान निराली होती है, वीआईपी मूवमेंट में पुलिस व प्रशासनिक बंदोबस्त में सरकारी काफिलों की पेट्रोल खपत में कहां कटौती होती है। वित्तीय बाधाएं जब तक पहचानी न गईं और जब तक सरकारी ढांचे में नौकरियों का दस्तूर छल करता रहा, हम अपने ही मुहानों पर लौटकर सिर मुंडवाएंगे। प्रदेश की पहली वित्तीय बाधा सार्वजनिक क्षेत्र का आवारा, गैर जिम्मेदार व अनुशासनहीन चरित्र है। अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम घाटे में हैं, लेकिन हम इन्हें राजनीतिक उद्देश्यों से पोषित कर रहे हैं।

अनावश्यक कार्यालय और विभिन्न संस्थान कर्ज की नैया में डूब रहे हैं। सरकारों की निजी क्षेत्र से दूरी तथा योजनाओं में उसकी भागीदारी से इनकार। सरकारी कर्मचारियों पर लगाया जा रहा वित्तीय सट्टा लगातार सरकारों की कमर तोड़ रहा है, जबकि यह मान लेना चाहिए कि यह वर्ग किसी सूरत 'मिशन रिपीट' नहीं करवा सकता। सरकारों की लगातार वापसी के लिए निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश, रोजगार के अवसर, स्वरोजगार का ढांचा और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रदर्शन को सक्षम बनाने के लिए नीतियों का निर्णायक होना जरूरी है।

राय

विपक्ष की थाली खाली नहीं

विपक्ष ने बजट को दुराग्रही, भेदभावी और सत्यानाशी तक करार दिया है। अंतिम शब्द घोर 'असंसदीय' है। विपक्ष की सोच बेहद नकारात्मक लगती है। विपक्ष के समवेत आरोप हैं कि गैर-भाजपा शासित राज्यों को ठन-ठन गोपाल रखा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनके हिस्से की राशि भी केंद्र सरकार जारी नहीं कर रही। ये भाजपा के राजनीतिक पूर्वाग्रह हैं, लिहाजा बजट संविधान-विरोधी, संघीय ढांचे के खिलाफ, राजनीतिक खुन्नस का बजट है। यह अन्यायपूर्ण है, किसान-गरीब विरोधी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा है कि आंध्रप्रदेश और बिहार की थालियों में पकौड़े-जलेबी परोसे गए हैं, शेष थालियां खाली हैं। करीब 90 फीसदी राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। खडग़े जैसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सांसद की यह टिप्पणी ही पूर्वाग्रही है, अतिरंजनापूर्ण है। उनसे सवाल है कि क्या इस तरह देश का आम बजट बनाया जा सकता है? यह संपूर्ण और राष्ट्रीय बजट राज्यों का निजी बजट नहीं है, बल्कि देश के संसाधनों और मंत्रालयों का हिसाब-किताब है। क्या यह भाजपा-एनडीए का घरेलू बजट है, जिसकी बंदरबांट कर ली गई? जहां तक बजट-भाषण में राज्यों के नाम का सवाल है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उप्र, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों का बजट-भाषण में उल्लेख तक नहीं किया। सरकार ने 'पूर्वोदय' योजना की घोषणा की है, जिसमें बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, आंध्रप्रदेश आदि राज्यों को रखा गया है। बहरहाल जिन राज्यों का जिक्र हमने किया है, उनमें से अधिकतर भाजपा-एनडीए शासित हैं।

वित्त मंत्री तो क्या, प्रधानमंत्री भी अपने ही पक्ष की थाली को खाली नहीं रख सकते। ऐसा नहीं किया जा सकता, यह विपक्ष भी जानता है, लिहाजा बजट के मुद्दे पर संसद परिसर में ही विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों का विरोध-प्रदर्शन, पोस्टरबाजी और नारेबाजी तथा दोनों सदनों से बहिर्गमन करना बेमानी है। आरोपों के पलटवार में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन योजनाओं का खुलासा किया है, जिनके लिए बजट में आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने 76,000 करोड़ रुपए की बंदरगाह का उल्लेख किया है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। उसका उल्लेख बजट में करना अनिवार्य है, क्योंकि बंदरगाह के लिए राशि जारी होनी है। उप्र के संदर्भ में बुंदेलखंड के 7 जिलों में प्राकृतिक खेती, कुल 12 औद्योगिक पार्कों में से 2 पार्क उप्र में, 1000 से अधिक आईटीआई में से 100 से अधिकतर ऐसे संस्थानों को उप्र में ही अपग्रेड किया जाना है, इंटर्नशिप योजना में 2 लाख से अधिक युवा उप्र के, मुफ्त अनाज योजना में सर्वाधिक लाभार्थी उप्र के, प्रधानमंत्री पक्का घर योजना के नए चरण में सबसे अधिक मकान उप्र में बनेंगे, 20000 करोड़ का कर्ज ब्याज के बिना 50 साल की अवधि के लिए और 2.23 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्रीय टैक्स में आदि ऐसे विषय हैं, जिनका उल्लेख बजट में है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पर भी विपक्ष के दावे ठीक नहीं हैं।

देश सेवा का जज्बा!

घर के बाहर किसी ने आकर तीन बार 'भारत माता की जय हो' नारे लगाए तो स्वाभाविक तौर पर मैं चौंका। बाहर आया तो देखा तीन-चार युवक थे। फिर उनमें से एक को गौर से देखा तो पहचान गया, वह गोपाल था। गोपाल मेरे दफ्तर में था। लेकिन हुलिया एकदम बदला हुआ था, चोला-पायजामा और सिर पर टोपी। मुझे देखते ही उसने मेरी चरण कमलों का स्पर्श किया और बोला- 'सर, आपका आशीर्वाद चाहिए।' मैंने कहा- 'भाई गोपाल वह तो सदैव तुम्हारे साथ रहा है, जब तुम दफ्तर में कामचोरी करते थे, तब भी मेरा आशीर्वाद था तुम्हें। परंतु तुमने अपना लिबास कब बदल लिया। मैं रिटायरमेंट के समय तो तुम्हें अच्छा-भला छोड़कर आया था।' वह बोला- 'सर, यह लिबास मैंने आज ही बदला है और आपको बताने आया हूं कि मैं चांदनी चौक से एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं।' मेरे नेत्र खुले के खुले रह गए और मैं बोला- 'चुनाव, लेकिन चुनाव लडऩे जैसी बात तो तुमने पहले कभी बताई नहीं थी। यह यकायक तुम्हें क्या हुआ है? मेरा मतलब तुमने नौकरी छोड़ दी है?' वह बोला- 'हां साहब, मैं देश सेवा करना चाहता हूं।' तब तक मैं थोड़ा सहज हो गया था, इसलिए बोला- 'वैरी गुड, देश सेवा भी बुरा धंधा नहीं है। इसमें हाथ डालोगे तो कुछ न कुछ बन भी जाओगे। लेकिन भाई इसमें तो पैसा बहुत चाहिए। पहले निवेश करो, तब रिटर्न सालों में मिलता है।' गोपाल बोला-'सर, मैं वाकई देश सेवा करना चाहता हूं।

अन्ना का भक्त हूं। उन्हीं की प्रेरणा से आज सब कुछ त्याग कर मैं मूल्यों की राजनीति करना चाहता हूं।' मैंने कहा-'वही तो मैं कह रहा था, राजनीति बिना मूल्य के आज करेगा भी कौन?' गोपाल ने मेरा छुपा व्यंग्य समझा नहीं और उत्साह से बोला-'सर, बस यही समझिए। दरअसल मैं भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध आवाज उठाकर चुनाव जीतने का दम भर रहा हूं। आप खुद देख रहे हैं, देश की हालत क्या हो रही है।' मैं बोला- 'गोपाल, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारे दोनों मुद्दे ज्वलंत हैं। इसमें गरीबी मिटाने जैसा तुर्रा और लगा लेते तो राह आसान हो जाती। मेरा मतलब भय, भ्रष्टाचार और भूख मिटाने से है।' गोपाल के होंठ थोड़ा हंसे और वह बोला-'सर भ्रष्टाचार और महंगाई, दोनों ही मुद्दे गरीब के लिए हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। धंधेबाज राजनेता देश को लूट रहे हैं और भारत चमकाने और भारत निर्माण की बातें कर रहे हैं। सर, इन सबका पर्दाफाश होना ही चाहिए।' मैंने देखा गोपाल का चेहरा तो उस पर ईमानदारी का जोश और व्यवस्था से लडऩे का जज्बा दिखाई दिया। मुझे गोपाल के बीवी-बच्चों का ख्याल आ गया कि अगर यह वाकई देख सेवा करने निकल गया तो वे क्या करेंगे? मैंने ही यही प्रश्न गोपाल पर दागा तो उसने कहा- 'सर, देश सेवा पहले है। बीवी-बच्चों को पेंशन बहुत है। अब मैं चुप नहीं रह सकता।' मुझे लगा गोपाल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का कोई फ्रीडम फाइटर है, जिसे अच्छा बनने का दौरा पड़ गया है।

मैं बोला- 'गोपाल, तुम स्वस्थ तो हो न। मेरा मतलब सोचने-समझने की तुम्हारी शक्ति कहीं लुप्त तो नहीं हो गई?' वह बोला- 'नहीं सर, मैं पूरे होशो-हवास में हूं। मैं देश को बदल डालूंगा। बहुत हो गया, धैर्य जवाब दे रहा है। ये मेरे साथी हैं।' मैंने शेष तीनों को देखा तो वे कुटिलता से मंद मुस्कान बिखेर रहे थे। मैंने कहा-'आप लोग गोपाल की बातों से सहमत हैं?' उनमें से एक बोला-'सर, हम लोग वर्षों से मूल्यों की राजनीति ही कर रहे हैं। जब तक इनके पास मूल्य हैं, हम लोग डटे रहेंगे।' मैं समझ गया ये आज के राजनेता हैं, जो गोपाल के रिटायरमेंट के बदले मिले पैसों तक के साथी हैं। बाद में ये लोग गोपाल को छोड़ देंगे। मैंने गोपाल से कहा-'गोपाल एक बार और सोच लेते। चुनाव थोड़ा ठहर कर लड़ लेते।' वह बोला-'नहीं सर, फिर देर हो जाएगी।' यह कह कर उसने तीन बार 'भारत माता की जय हो' के नारे का उद्घोष किया और चला गया। मैंने मन ही मन कहा-'बेचारा गोपाल। भगवान उसकी रक्षा करे।' मैं भारी मन से अंदर आ गया। बार-बार मेरी आंखों में गोपाल का चेहरा घूम रहा था। उसकी देश सेवा के जज़्बे को बार-बार नमस्कार।

दक्षताओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कक्षा 9-12 के लिए एनसीईआरटी द्वारा समग्र प्रगति कार्ड

विजय गर्ग

राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख ने हाल ही में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों (कक्षा IX-XII) के लिए एक समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) जारी किया है। स्कूली छात्रों के बीच दक्षताओं को संरेखित करने और विकसित करने के उद्देश्य से एचपीसी को छात्रों के बीच आत्म-चिंतन, अनुसंधान कौशल, प्रवेश परीक्षा की तैयारी और समय प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसे छात्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन के बाद भरा जाएगा। एचपीसी को अंतिम रूप देते समय शिक्षक और परामर्शदाता दक्षताओं का आकलन करेंगे और फीडबैक देंगे। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप एचपीसी विकसित किया है। रूपरेखा का उद्देश्य बहु-विषयक शिक्षा शुरू करना, रचनात्मक शिक्षाशास्त्र को बढ़ावा देना और पारंपरिक कलम-और-कागज परीक्षाओं से परे छात्रों के समग्र विकास का पोषण करना है। एनसीईआरटी को व्यक्तित्व निर्माण, आंतरिक कौशल विकसित करने और दीर्घकालिक कैरियर लक्ष्यों के निर्माण में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड के साथ एकीकृत करने की भी उम्मीद है। "एचपीसी में माध्यमिक चरण छात्रों को लक्षित तरीके से करियर विकल्प चुनने में मदद करने पर केंद्रित है। प्रगति कार्ड छात्रों की कार्य क्षमता से जोड़ने के लिए उनकी रुचि का आकलन करता है। कार्ड में इस बारे में प्रश्न शामिल हैं कि छात्र एक, दो या दस वर्षों में खुद की कल्पना कैसे करते हैं, साथ ही उनकी प्रगति, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी और एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल के बारे में पूछताछ भी शामिल है। शिक्षक और परामर्शदाता इन अनुभागों को पूरा करने में छात्रों की सहायता करेंगे ताकि उन्हें अपने करियर लक्ष्यों का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद मिल सके, "प्रोफेसर इंद्राणी भादुड़ी, सीईओ परख और प्रमुख, शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग, एनसीईआरटी ने कहा। एनसीईआरटी ने एचपीसी के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं चलाना शुरू कर दिया है। "हम माध्यमिक स्तर पर प्रगति कार्ड के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य बोर्डों और एससीईआरटी के साथ बातचीत कर रहे हैं। कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने पहले ही प्रक्रिया शुरू करने और शिक्षकों की मदद के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने में रुचि दिखाई है। शैक्षणिक दबाव को संबोधित करना बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों पर शैक्षणिक दबाव को कम करने और अधिक समग्र शिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए, परख एचपीसी को बोर्ड परिणामों में एकीकृत करने की भी योजना बना रहा है। "हम बोर्ड परिणामों की समानता पर भी काम कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम एचपीसी को बोर्ड परिणामों के साथ विलय करने की योजना बना रहे हैं। इससे छात्रों पर शैक्षणिक तनाव को कम करने में मदद मिलेगी और परीक्षा भय का

भी समाधान होगा जिसका छात्रों को सामना करना पड़ता है, खासकर दसवीं और बारहवीं कक्षा में, "भादुड़ी कहते हैं, परख ने शिक्षा मंत्रालय को बोर्ड में समकक्ष प्रक्रिया का विवरण सौंप दिया है। परीक्षा। एचपीसी के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। एनसीईआरटी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए प्रत्येक शैक्षिक ब्लॉक से 'मास्टर ट्रेनर' नियुक्त करेगा। "शिक्षकों को एचपीसी के एक नमूने द्वारा समर्थित किया जाएगा जो उन्हें इसके आवश्यक अनुभागों और इसके कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को समझने में मदद करेगा। हम जिला स्तर पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए विभिन्न बोर्डों, शिक्षा निदेशालय और एससीईआरटी से जुड़ रहे हैं। इन सत्रों में प्रशिक्षित लोगों को मास्टर ट्रेनर कहा जाएगा, जो फिर शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, "भादुड़ी कहते हैं। प्रशिक्षण सत्र शिक्षकों को गहनता से सुसज्जित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैंएचपीसी का ज्ञान, जो उन्हें उन छात्रों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में सक्षम करेगा जिन्हें प्रगति कार्ड भरने में कठिनाई हो सकती है। सत्र शिक्षकों को अपने शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ाने और छात्रों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समर्थन करने के लिए नवीन समाधान अपनाने में भी मदद करेंगे। करियर पर ज्यादा फोकस मार्च में, परख ने प्राथमिक छात्रों की समझ और रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से, बुनियादी, मध्य और प्रारंभिक चरणों के लिए एचपीसी की शुरुआत की। माध्यमिक चरण के लिए, परख द्वारा विकसित एचपीसी व्यावसायिक शिक्षा और कैरियर विकल्पों पर अधिक जोर देता है। एचपीसी में ऐसे अनुभाग शामिल हैं जो छात्रों द्वारा किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, उनके पेशेवर हितों, करियर योजनाओं और उनके करियर विकल्पों के आत्म-मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं। रिसर्च पर जोर एचपीसी की एक विशिष्ट विशेषता इसका व्यक्तिगत अनुसंधान और सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना है। छात्रों को एचपीसी में शोध करते समय अपनी पसंद के विषय पर शोध करना होगा और सीखने की प्रक्रिया को भरना होगा। "शोध विषय को छात्र अपनी पसंद के विषयों में से चुन सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा पैदा करना और परिकल्पना विकसित करने और उनके समर्थन में साक्ष्य ढूंढने की क्षमता बढ़ाना है। एचपीसी परिणाम की तुलना में अनुसंधान प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। अनुसंधान के सभी चरणों के लिए, हमारे पास शिक्षकों का मूल्यांकन और शिक्षार्थी का प्रतिबिंब है, जो शिक्षक-शिक्षार्थी संबंधों पर जोर देता है। डिजिटल शिक्षा एचपीसी के हिस्से के रूप में छात्रों की पसंद के विषयों में कौरसेरा और एमओओसी जैसे प्लेटफार्मों से अल्पकालिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। "कक्षाओं को स्मार्ट बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को धन दिया जाता है। फिर भी, कई ग्रामीण छात्र डिजिटल पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करने में सक्षम नहीं हैं। एचपीसी का एक खंड उद्यमिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर डिजिटल पाठ्यक्रमों के पंजीकरण और पूरा करने पर केंद्रित है। शिक्षक छात्रों को डिजिटल पाठ्यक्रमों पर पंजीकरण करने और उनकी प्रगति का आकलन करने में सहायता करेंगे।" यह पहल छात्रों को डिजिटल शिक्षा तक पहुंचने और कक्षाओं से परे कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। "यह विचार ग्रामीण और शहरी शिक्षार्थियों के बीच अंतर को पाटना है। जो छात्र शहरों से आते हैं वे ऐसे पाठ्यक्रमों के बारे में जानते हैं जिनका उपयोग वे अपनी रुचि के विषयों के बारे में अधिक जानने के लिए कर सकते हैं। हालाँकि, ग्रामीण इलाकों में ऐसे पाठ्यक्रमों के बारे में जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतर है। डिजिटल लर्निंग पर जोर देने से इन कमियों को भरने में मदद मिलेगी।"

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स में क्यों किया बदलाव, राजस्व सचिव ने दिए सवालों के जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

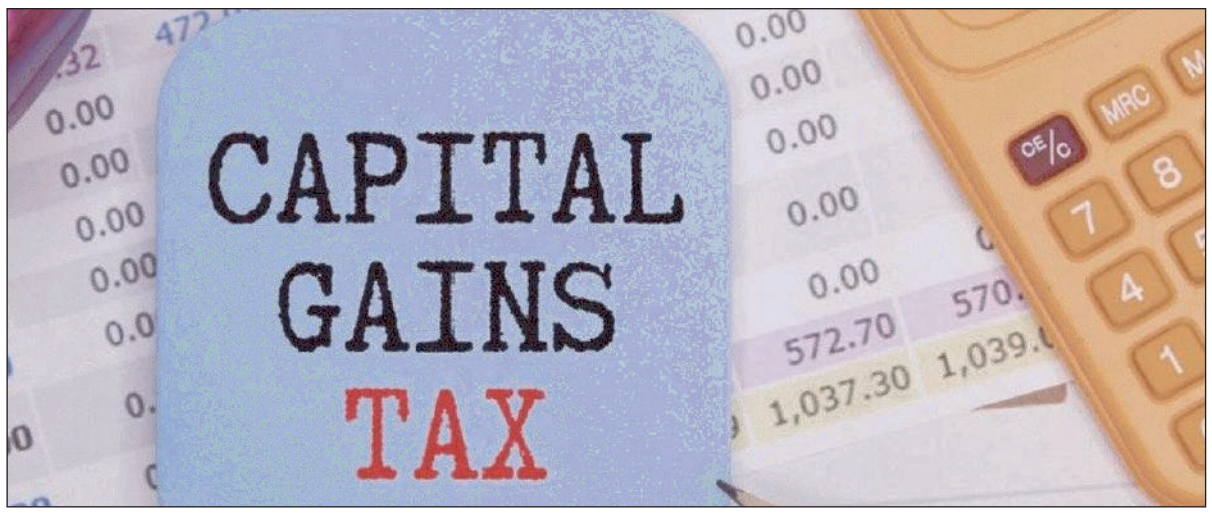

दरों के संदर्भ में एलटीसीजी को महंगाई के प्रभाव को समाहित करने वाले (इंडेक्सेशन) लाभ के बगैर सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए 12 .5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)-भुगतान वाली इक्विटी को छोड़कर सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए यह दर 20 प्रतिशत थी। अचल संपत्ति के मामले में यह इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत थी।

नई दिल्ली। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव उद्योग जगत की मांग पर लाया गया है। राजस्व सचिव ने उद्योग संगठनों सीआइआई और एसोचैम के सदस्यों को संबोधित करते हुए यह जानना चाहा कि क्या उद्योग जगत विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए कर की अलग-अलग दरों के पक्ष में है।

LTCG के लिए होल्डिंग अवधि दो साल

मंगलवार को संसद में पेश वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों को रखने की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया है। सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों के लिए होल्डिंग अवधि अब दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) के लिए एक वर्ष कर दी गई है जबकि गैर-सूचीबद्ध शेयरों, डिबेंचर और रियल एस्टेट के मामले में एलटीसीजी के लिए होल्डिंग अवधि दो साल है।

परिवर्तन एक सरलीकरण उपाय

दरों के संदर्भ में एलटीसीजी को महंगाई के प्रभाव को समाहित करने वाले (इंडेक्सेशन) लाभ के बगैर सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)-भुगतान वाली इक्विटी को छोड़कर सभी परिसंपत्ति वर्गों के लिए यह दर 20 प्रतिशत थी। अचल संपत्ति के मामले में यह इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत थी। करों में किए गए बदलावों पर उठे विवादों के बीच मल्होत्रा ने कहा, 'पूंजीगत लाभ कर में परिवर्तन एक सरलीकरण उपाय है और यह राजस्व वृद्धि का कदम नहीं है।

इससे राजस्व में वृद्धि हुई है लेकिन वह बहुत ही मामूली है। यह करों को सरल बनाने की पहल है जिसकी आप सभी (उद्योग) ने मांग की थी।' उन्होंने सरलीकरण से अनुपालन बोझ में कमी आने का जिक्र करते हुए कहा कि करों को सरल बनाने का मतलब यह नहीं है कि हर मामले में कर बोझ कम हो जाएगा और करदाता को हर पहलू में लाभ ही होगा, चाहे वह होल्डिंग अवधि हो या सबसे कम दरें हों।

मल्होत्रा ने कहा, 'ऐसा नहीं होगा क्योंकि आखिरकार सरकार को भी राजस्व की जरूरत है। इसलिए जब आप सरलीकरण की मांग कर रहे हैं तो हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कुछ चीजें बढ़ेंगी और कुछ चीजें घटेंगी।' उन्होंने उद्योग से पूछा कि क्या शेयरों को बेचने से होने वाले लाभ और समान अवधि के लिए रखे गए डिबेंचर या रियल एस्टेट संपत्तियों को बेचने से होने वाले लाभ पर कर की दर अलग-अलग होनी चाहिए।

मल्होत्रा ने कहा कि सीआइआई ने बजट से पहले सरकार को दिए अपने ज्ञापन में एलटीसीजी पर दो कर दरें रखने की मांग की थी लेकिन बजट में केवल एक कर दर लाकर इस व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत बना दिया गया है।

एलटीसीजी पर विभाग ने दिया स्पष्टीकरण

अगर आपने कोई संपत्ति 2001 से पहले खरीदी थी, तो उसे बेचते समय उस पर लगने वाले टैक्स की गणना करते वक्त 2001 की कीमतों को आधार माना जाएगा, या फिर आपने जितने में खरीदी थी, उसमें 2001 तक की महंगाई दर जोड़कर निकाली गई कीमत, इन दोनों में से जो भी कम हो, उसे माना जाएगा। आयकर विभाग ने एक उदाहरण देकर बताया कि 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के मामले में पूंजीगत लाभ कर की गणना कैसे की जाएगी।

इसने एक ऐसी संपत्ति का उदाहरण दिया, जिसकी 1990 में खरीद की लागत पांच लाख रुपये थी और एक अप्रैल, 2001 को इसका स्टांप ड्यूटी मूल्य 10 लाख रुपये था और फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपये थी। अगर इसे 23 जुलाई, 2024 को या उसके बाद एक करोड़ रुपये में बेचा जाता है तो एक अप्रैल, 2001 को अधिग्रहण की लागत 10 लाख रुपये (स्टांप ड्यूटी या एफएमवी में से जो भी कम हो) होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत (इंडेक्सड कास्ट) 36.3 लाख रुपये है। ऐसे मामलों में एलटीसीजी 63.7 लाख रुपये (1 करोड़ रुपये माइनस 36.3 लाख रुपये) पर लगेगा। 20 प्रतिशत की कर दर पर ऐसी संपत्तियों के लिए एलटीसीजी कर 12.74 लाख रुपये होगा।

Paytm और SJVN जैसी 5 कंपनियां, जिनके शेयरों में दिखी सबसे ज्यादा हलचल

आज पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97कम्युनिकेशंस के शेयरों में 10 फीसदी का अपर सर्किट लगा। यह 509 .05 रुपये पर बंद हुआ। इसे एक प्रमुख सहायक कंपनी में 50 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। SJVN के स्टॉक में आज 11 फीसदी से अधिक का उछाल दिखा। आइए बाकी कंपनियों के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। पिछले पांच दिनों से भारतीय शेयर मार्केट लाल निशान में बंद रहे थे। लेकिन, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को यह सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 1,292 अंक यानी 1.6 फीसदी चढ़कर 81,332 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 428 अंक यानी 1.8 फीसदी के उछाल के साथ 24,834 पर पहुंच गया। आज तकरीबन 2,407 शेयरों में तेजी, 1,203 शेयरों में गिरावट और 90 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

आइए पांच शेयरों के बारे में जानते हैं, जिनके शेयरों में सबसे अधिक हलचल देखने को मिली।

पेटीएम का दिखा जलवा

आज पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97कम्युनिकेशंस के शेयरों में 10 फीसदी का अपर सर्किट लगा। यह 509.05 रुपये पर बंद हुआ। इसे एक प्रमुख सहायक कंपनी में 50 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है।

SJVN में जबरदस्त तेजी

SJVN के स्टॉक में आज 11 फीसदी से अधिक का उछाल दिखा। कंपनी ने बताया कि उसे दार्जो लुई पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के आवंटन के लिए मिजोरम सरकार से पत्र मिला है।

Cyient 9 फीसदी लुढ़का

Cyient के शेयर आज 9 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए। दरअसल, कंपनी की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजों से निवेशकों निराश किया। इस आईटी कंपनी ने एनालिस्टों के अनुमान के मुकाबले रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में काफी कमी दर्ज की है।

सिप्ला में दिखी जोरदार तेजी

Cipla सिप्ला के आज लगभग 6 प्रतिशत के उछाल के साथ 1,586.50 रुपये पर बंद हुए। कंपनी ने जून में खत्म तिमाही के लिए अपने नेट प्रॉफिट में 17 फीसदी की सालाना वृद्धि की जानकारी। राजस्व में 6 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इससे निवेशकों का हौसला बढ़ा और उन्होंने जमकर खरीदारी की।

श्रीराम फाइनेंस 10 फीसदी उछला

Shriram Finance के शेयर में आज करीब 10 फीसदी बढ़कर 2,934 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी ने पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे निवेशक जोश में दिखे। जून तिमाही में कंपनी को 2,022.8 करोड़ रुपये प्रॉफिट हुआ है। यह एक साल पहले के मुकाबले 19 प्रतिशत अधिक है।

पेटीएम को अब तक नहीं मिली पेमेंट एग्रीगेटर में निवेश की अनुमति, विचाराधीन है प्रस्ताव

पेटीएम की मूल कंपनी 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) में चीन से निवेश है। इसलिए विदेश गृह वित्त और उद्योग मंत्रालयों के अधिकारियों वाला अंतर-मंत्रालयी पैनल इस बात पर विचार कर रहा है कि 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) का पीपीएसएल में निवेश प्रस्ताव एफडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार है या नहीं। प्रस्ताव अभी भी अंतर-मंत्रालयी पैनल के विचाराधीन है और जल्द ही इस पर फैसला होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। चीन से जुड़े निवेशों की निगरानी करने वाले अंतर-मंत्रालयी पैनल ने अभी तक Paytm के अपने भुगतान एग्रीगेटर ब्रांच में निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। एक आला अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है।

जल्द फैसले की उम्मीद

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि प्रस्ताव अभी भी अंतर-मंत्रालयी पैनल के विचाराधीन है और जल्द ही इस पर फैसला होने की उम्मीद है। संकटग्रस्त पेटीएम ने अपनी 100 प्रतिशत सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) में 50 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।

पेटीएम की मुल कंपनी 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) में चीन से निवेश है। इसलिए, विदेश, गृह, वित्त और उद्योग मंत्रालयों के अधिकारियों वाला अंतर-मंत्रालयी पैनल इस बात पर विचार कर रहा है कि 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) का पीपीएसएल में निवेश प्रस्ताव एफडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार है या नहीं।

RBI से कब मिलेगी अनुमति?

जोशी ने कहा कि एक बार अंतर-मंत्रालयी पैनल इसे मंजूरी दे देता है, तो पेटीएम भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के अनुदान के लिए आरबीआई से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक उनके प्रस्ताव की जांच करेगा और लाइसेंस देने या न देने पर फैसला करेगा।

एक बार खारिज हो चुका है आवेदन

पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ने नवंबर 2020 में भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देशों के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

हालांकि, टॉप ब्रांच ने नवंबर 2022 में पीपीएसएल के आवेदन को खारिज कर दिया। आरबीआई ने कंपनी को एफडीआई नियमों के तहत प्रेस नोट 3 का अनुपालन करने के लिए इसे फिर से जमा करने को कहा है। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) में चीनी फर्म एंट ग्रुप कंपनी का निवेश है।

लगातार तीन दिन दाम गिरने के बाद आज महंगा हुआ सोना, चांदी भी चमकी

परिवहन विशेष न्यूज

शुक्रवार को सोना 50 रुपये बढ़कर 70700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं गुरुवार को पिछले सत्र में गोल्ड की कीमत 70650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी भी 400 रुपये उछलकर 84400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले बंद भाव में यह 84000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वैश्विक बाजार में भी इनकी कीमतें बढ़ी हैं।

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के कारण स्थानीय बाजार में सोने की कीमतों में पिछले तीन सत्रों की गिरावट के बाद शुक्रवार को तेजी लौटी है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है।

महंगा हुआ सोना

शुक्रवार को सोना 50 रुपये बढ़कर 70,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं, गुरुवार को पिछले सत्र में गोल्ड की कीमत 70,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 50-50 रुपये बढ़कर क्रमशः 70,700 रुपये और 70,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

चांदी भी 400 रुपये उछलकर 84,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले बंद भाव में यह 84,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। कारोबारियों ने सोने की कीमतों में तेजी का श्रेय घरेलू बाजार में आभूषण विक्रेताओं की मांग में तेजी और विदेशी बाजारों में मजबूत रुख को दिया। गुरुवार को सोने की कीमतों में 1,000 रुपये की भारी गिरावट आई और यह 70,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई, जबकि चांदी 3,500 रुपये गिरकर 84,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

सीमा शुल्क कम होने के बाद घटे दाम

सरकार ने मंगलवार को घोषणा की थी कि सोने और चांदी सहित कई उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत हो गई है। घोषणा के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 3,350 रुपये गिरकर 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 3,500 रुपये गिरकर

87,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का वायदा भाव 294 रुपये या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 67,756 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। सबसे अधिक कारोबार वाला अगस्त अनुबंध 528 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया और 67,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके अलावा, एक्सचेंज पर सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी का अनुबंध 59 रुपये या 0.07 प्रतिशत बढ़कर 81,390 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

विदेशी बाजारों का हाल

विदेशी बाजारों में कॉमेक्स सोना 2,416.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स गोल्ड को 2,350 अमेरिकी डॉलर के आसपास समर्थन मिलने के साथ सोने की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि, न्यूयॉर्क में चांदी मामूली रूप से गिरकर 27.89 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर आ गई। हाल ही में येन में तेजी और मुद्रा में सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी के कारण कीमतों में गिरावट आई है।

वेदांता ने दूसरे अंतरिम डिविडेंड की दी मंजूरी, शेयरहोल्डर्स की होगी बंपर कमाई

माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड डिविडेंड देने के लिए मशहूर है। कंपनी ने एक बार फिर मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 के डिविडेंड का एलान किया है। अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल के मालिकाना हक वाली ने शुक्रवार को बोर्ड मीटिंग के दौरान दूसरे अंतरिम डिविडेंड की मंजूरी दी। आइए जानते हैं कि कंपनी कब और कितना डिविडेंड देने वाली है।

नई दिल्ली। डिविडेंड देने के लिए मशहूर वेदांता लिमिटेड ने शुक्रवार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का एलान किया है। वेदांता लिमिटेड ने बीएसई को एक फाइलिंग में बताया कि डिविडेंड के लिए कुल 1,564 करोड़ रुपये का पेमेंट किया जाएगा। अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल के मालिकाना हक वाली ने शुक्रवार को बोर्ड मीटिंग के दौरान दूसरे अंतरिम डिविडेंड की मंजूरी दी।

वेदांता ने जुटाए 8,500 करोड़ रुपये

पिछले दिनों ने माइनिंग सेक्टर के दिग्गज ग्रुप वेदांता लिमिटेड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 1 अरब डॉलर यानी 8,500 करोड़ रुपये जुटाए। इसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए), गोल्डमैन सैक्स एएमसी, निप्पॉन म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे प्रमुख निवेशकों को क्यूआईपी के माध्यम से इक्विटी शेयर आवंटित किए गए।

वेदांता ने कई मोर्चों पर मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और वृद्धि दर्ज की है। इसके एल्यूमीनियम, जस्ता, चांदी, इस्पात, लौह अयस्क और फेरोक्रोम जैसे कई व्यवसायों - पिछले वित्त वर्ष में अपने उच्चतम वार्षिक उत्पादन स्तर को हासिल किया। वेदांता के शेयर शुक्रवार को 3.79 फीसदी के उछाल के साथ 447.25 रुपये पर बंद हुए।

गोल्ड माइनिंग में प्राइवेटाइजेशन की मांग

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सोने की सरकारी खदानों का निजीकरण करने की मांग की। अग्रवाल ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। हम अपनी जरूरत का 99.9% आयात करते हैं। बड़े पैमाने पर निवेश के साथ, हम सोने के एक प्रमुख उत्पादक और रोजगार के बड़े स्रोत बन सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, सरकार सोने के दो एकमात्र उत्पादकों, भारत गोल्ड माइन और हट्टी गोल्ड माइन का निजीकरण कर दे।'

अग्रवाल ने निजीकरण की शर्तों भी बताईं। उन्होंने कहा, निजीकरण तीन शर्तों के साथ होना चाहिए। पहला, छंटनी नहीं की जाएगी। दूसरा, कर्मचारियों को कुछ इक्विटी दी जाएगी। तीसरा, इसे अलग-अलग हिस्सों में परिसंपत्तियों को बांटने के किसी भी प्रयास के बिना किया जाना चाहिए।'

आईटी सेक्टर में वापस आने वाली है नौकरियों की बहार, 90 हजार फ्रेशर्स को जॉब देंगी TCS-इन्फोसिस जैसी कंपनियां

मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 के दौरान देश की दिग्गज आईटी कंपनियां करीब 90 हजार फ्रेशर्स की हायरिंग करने वाली हैं। सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस करीब 40 हजार और इन्फोसिस 15-20 हजार फ्रेशर्स को नौकरी देने पर विचार कर रही है। वहीं एचसीएल टेक 10 हजार विप्रो 10-12 हजार और टेक महिंद्रा छह हजार फ्रेशर्स की हायरिंग कर सकती है।

नई दिल्ली। पिछले काफी समय से आईटी सेक्टर में हायरिंग की प्रक्रिया काफी सुस्त थी। लेकिन, अब इसमें फिर से तेजी आने की उम्मीद है। आईटी कंपनियों के तिमाही काफी अच्छे रहे। इससे डिमांड बढ़ने का संकेत मिलता है। ऐसे में आईटी कंपनियां हायरिंग बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 के दौरान देश की दिग्गज आईटी कंपनियां करीब 90 हजार फ्रेशर्स की हायरिंग करने वाली हैं। सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) करीब 40 हजार और इन्फोसिस 15-20 हजार फ्रेशर्स को नौकरी देने पर विचार कर रही है। वहीं, एचसीएल टेक 10 हजार, विप्रो 10-12 हजार और टेक महिंद्रा छह हजार फ्रेशर्स की हायरिंग कर सकती है।

जून तिमाही में कितनी हायरिंग

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2024 के दौरान टीसीएस ने 5,452 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा है। इसके साथ कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 6,06,998 हो गई है। कंपनी के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मिलिंद लक्कड़ के अनुसार, कंपनी सीधे कैंपस से फ्रेशर्स को हायरिंग करने की रणनीति बना रही है।

इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 11,900 फ्रेशर्स को नौकरी दी है। वित्त वर्ष 2022-23 में 50 हजार फ्रेशर्स की हायरिंग के मुकाबले इसमें 76 प्रतिशत की कमी रही है।

NEET-UG का संशोधित रिजल्ट जारी, 61 से घटकर 17 हुई टॉपरों की संख्या

परिवहन विशेष न्यूज

नीट-यूजी का अंतिम संशोधित परिणाम जारी हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रिजल्ट जारी किया। दिल्ली के मृदुल मान्या ने पहले स्थान पर जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले आयुष नौग्रेय अब दूसरे स्थान पर आए हैं। पात्रता हासिल करने वालों की संख्या में भी गिरावट आई है।

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आखिरकार मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट-यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें न सिर्फ टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 पर आ गई है, बल्कि पात्रता हासिल करने वाले छात्रों की संख्या भी 13.16 लाख से घटकर 13.15 लाख हो गई है।

मृदुल मान्या ने किया टॉप

टॉपर्स में अब दिल्ली के मृदुल मान्या आनंद शीर्ष वरीयता पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के आयुष नौग्रेय हैं। इससे पहले टॉपर्स की सूची में मृदुल ने तीसरे और आयुष ने चौथे नंबर पर जगह बनाई थी। समान अंक आने पर शीर्ष स्थान की यह वरीयता तय करने में पहले छात्रों के भौतिकी, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान के अंकों पर विचार किया जाता है। उनके भी अंक समान होने पर छात्रों की उम्र और परीक्षा में उसके प्रयासों की संख्या पर विचार होता है।

कटऑफ भी आया नीचे

संशोधित रिजल्ट में कटऑफ भी नीचे आया है। सामान्य श्रेणी का कटऑफ अब न्यूनतम 164 अंक से घटकर 162 अंक पर आ गया है। एनटीए ने शुक्रवार को नीट-यूजी का यह संशोधित रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया है। जिसमें फिजिक्स के एक सवाल के दो सही जवाब पाए जाने पर एनटीए ने दोनों जवाबों में से कोई एक जवाब देने वाले सभी छात्रों को उसके पूरे नंबर दे दिए थे लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।

सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर जारी हुआ संशोधित रिजल्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को सवाल के विकल्पों में से सही जवाब बताने को कहा। इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने एक विकल्प को सही बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नए सिरे से संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था।

4.20 लाख छात्रों पर पड़ा असर

इस फैसले के बाद सवाल का गलत जवाब देने वाले 4.20 लाख छात्रों के पांच अंक कम कर दिए गए। इनमें जहां चार अंक सही जवाब के थे, वहीं एक अंक गलत जवाब देने का था। इस एक सवाल के गलत होने का असर वैसे तो 4.20 लाख छात्रों पर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर 50 हजार से एक लाख तक की रैंकिंग में आने वाले करीब 16 हजार छात्रों पर पड़ा है। हो सकता है कि इसके चलते उन्हें अब किसी कॉलेज में दाखिला भी न मिल पाए।

यहां समझे रैंकिंग और सीट का गणित

वैसे भी देश में मौजूदा समय में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल सीटों को मिलाकर देखें तो वे करीब एक लाख हैं। ऐसे में किसी छात्र की रैंकिंग अगर एक लाख से नीचे गई है तो उसे किसी भी कॉलेज में दाखिला मिलना मुश्किल होगा। वहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल सीटें लगभग 50 हजार हैं, ऐसे में यदि इससे नीचे किसी की रैंकिंग गई तो उसे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा।

चार जून को पहली बार जारी हुआ था रिजल्ट

गौरतलब है कि पांच मई को आयोजित नीट-यूजी का रिजल्ट वैसे तो चार जून को लोकसभा चुनाव परिणामों के बीच ही जारी हो गया था। मगर बाद में इस परीक्षा को लेकर एक-एक कर नई गड़बड़ियां सामने आईं। इनमें छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने और परीक्षा में जुड़ी अन्य गड़बड़ियों का भी मामला था। विवाद बढ़ने पर एनटीए ने 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए थे। साथ ही उन्हें बाद में फिर परीक्षा का मौका दिया गया था। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को आयोजित की गई थी और उनके नए सिरे रिजल्ट भी घोषित किए गए थे।

कब खड़ा हुआ विवाद

नीट-यूजी को लेकर पूरा विवाद तब खड़ा हुआ जब एक साथ 67 छात्रों के नाम टॉपर्स की लिस्ट में देखने को मिले। मेरिट लिस्ट में कुछ छात्रों के नंबर कुल 720 में से 718 व 719 जैसे दिए गए। जबकि परीक्षा में एक सवाल के सही होने पर चार अंक मिलते हैं और गलत होने पर मिले अंकों में से एक अंक कम हो जाता है। ऐसे में इन अंकों को लेकर भी सवाल गरमाया।

एनटीए ने दिया था ग्रेस मार्क्स

एनटीए की ओर से बताया गया कि छात्रों को परीक्षा में कम समय मिला था, इसके चलते उन्हें ग्रेस मार्क्स देने से ऐसे अंक देखने को मिल रहे थे। बाद में जैसे ही परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने की व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा उठा और वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एनटीए ने उसे वापस ले लिया। ऐसे में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 पर आ गई थी।

शीर्ष स्थान पाने वाले 17 छात्र

1. मृदुल मान्या आनंद- दिल्ली
2. आयुष नौग्रेय- उत्तर प्रदेश
3. माजिन मंसूर- बिहार
4. प्रचिता- राजस्थान
5. सौरव- राजस्थान
6. दिव्यांश- दिल्ली
7. गुंमय गर्ग- पंजाब
8. अर्घ्यदीप दत्ता- बंगाल
9. शुभन सेनगुप्ता- महाराष्ट्र
10. आर्यन यादव- उत्तर प्रदेश
11. पलंशा अग्रवाल- महाराष्ट्र
12. रजनीश पी.- तमिलनाडु
13. श्रीनंद शर्मिल- केरल
14. माने नेहा कुलदीप- महाराष्ट्र
15. तेजस सिंह- चंडीगढ़
16. देवेश जोशी- राजस्थान
17. इरम काजी- राजस्थान

नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इसी साल आ जाएगी अस्तित्व में

विजय गर्ग, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर इंतजार अब खत्म होगा। इस साल के अंत तक यह अस्तित्व में आ जाएगी। केंद्र सरकार ने बजट में इसके गठन के लिए सौ करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया है। यह विश्वविद्यालय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर व अध्ययन सामग्री आदि जुटाने पर खर्च होगा। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का एलान केंद्र सरकार ने 2022 में किया था। 2023- 24 में सरकार ने अपने बजट में इसके गठन के लिए सिर्फ चार करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इस बीच, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन से जुड़ी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। साथ ही इसका ढांचा भी तैयार कर लिया गया है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश के सभी शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े कोर्स मुहैया कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके संचालन के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का भी स्वरूप तैयार कर लिया गया है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सचिव सहित उच्च शिक्षा सचिव, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय के दो-दो कुलपति और दो अन्य शिक्षाविद को रखने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि बजट में नए आवंटन के बाद अब इसके गठन में तेजी आएगी। जल्द ही प्रशासनिक भवन तैयार करने सहित तकनीकी सुविधाओं को जुटाया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी होने बड़े कैंपस की जरूरत नहीं होगी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा पर सैकड़ों ट्रक रोके गए हैं

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर : पश्चिम बंगाल से आलू ओडिशा नहीं आ सकता । पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा पर सैकड़ों ट्रक रोके गए हैं । पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा हिरासत। ऐसा नजारा लक्ष्मण नाथ टोल प्लाजा अनंती के पास देखने को मिला है । गौरतलब है कि जहां ओडिशा आलू के लिए पश्चिम बंगाल पर निर्भर है, वहीं लगातार कुछ दिनों से आलू को लेकर राजनीति शुरू हो गई है ।20 रुपये प्रति किलो अब 45 रुपये तक पहुंच गया है । इसकी वजह पश्चिम बंगाल सरकार है. सूचना है कि रास्ता न होने के कारण ट्रक नहीं आ सकता। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सभी लेनों की जांच की है और उन्हें पश्चिम बंगाल सीमा पर चौकियों पर रोक दिया है। हालाँकि, यह पाया गया कि ओडिशा की ओर जाने वाले आलू से भरे सैकड़ों ट्रकों को सीमा पर रोक दिया गया था। हालांकि, वाहन के चालक और सहायकों ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल प्रशासन ने हिरासत में लिया था।

'यूपी में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है', दिल्ली में CM योगी की बैठक से पहले संजय सिंह का दावा

उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इन सबके बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिन के दिल्ली दौरे पर आएंगे लेकिन उससे पहले AAP के नेता संजय सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा और सरकार की अंदरुनी लड़ाई सबके सामने है।

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव में आए रिजल्ट के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत उफान पर है। भाजपा की अंदरुनी लड़ाई अब खुल कर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद ही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा।

जल्द ही योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जाएगा-संजय सिंह

संजय सिंह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह (Amit Shah) के इशारे पर चल रहा है और जल्द ही योगी आदित्यनाथ जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा।

सरकार गिराने के लिए विंटर डिस्काउंट भी देंगे- अखिलेश यादव

बीते दिन ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 100 लाओ, सरकार बनाओ का मानसून ऑफर देने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यंग्य करते हुए कहा कि सरकार गिराने के लिए वह विंटर डिस्काउंट भी देंगे। एक चैनल को दिए साक्षात्कार में सपा मुखिया ने कहा कि जब तक सरकार नहीं गिर जाती कोई न कोई ऑफर तो देना ही पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दो-तीन दिन में बन जाएगा।

संगम विश्वविद्यालय में नए आपराधिक कानून पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। संगम विश्वविद्यालय, जिसे शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, के विधि विद्यालय ने 26 जुलाई, 2024 को नए आपराधिक कानून पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. करुणेश सक्सेना द्वारा की गई, जिन्होंने छात्रों को संबोधित किया और कार्यशाला की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. मानस रंजन पाणीग्रही ने छात्रों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अध्ययन और उन्नति के लिए प्रेरित किया। रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉ. राजीव मेहता ने इस कार्यशाला को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री विशाल भार्गव, अतिरिक्त जिला नयायाधीश एवं सचिव , ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्रों को नए अपराधिक कानून के बारे में संबोधित करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में इन बदलावों के महत्व पर चर्चा की।

कार्यशाला के विशिष्ठ अथिति रिटायर्ड न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 में हुए परिवर्तन पर छात्रों को मार्गदर्शन दिया। इस कार्यशाला में भीलवाड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता श्री ऋषि तिवारी ने भी नए कानूनों पर चर्चा की।

इस कार्यशाला की पहली वक्ता डॉ. श्वेता सिंह, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लॉ, पुणे से, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) पर अपने विचार साझा किए। उनके व्याख्यान ने कानून की शिक्षा में नवाचार और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

दूसरी वक्ता डॉ. अनु सोलंकी, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता, ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पर चर्चा की और न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया।

इस प्रतियोगिता के संयोजक डॉ. ओमप्रकाश सोमकुंवर और सह संयोजक श्री गौरव सक्सेना रहे। इस कार्यक्रम में डॉ. सुनाक्षी शर्मा, अवतार चौबे, शशांक शेखर सिंह, आदित्य दाधीच, वर्तिका मिश्रा, डॉ. गोवर्धन लाल पांडे, डॉ. श्रीजया पाटिल और डॉ. विष्णुप्रिया दाधीच का इस कार्यशाला को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंच का संचालन दीक्षा दुग्गर ने किया। श्री गौरव सक्सेना ने कार्यशाला के समापन पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

एस-400 सुदर्शन ने दिखाई ताकत, अभ्यास में 'दुश्मन' के 80 फीसदी विमानों को 'मार गिराया'

सुदर्शन एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने हाल ही में एक अभ्यास में बड़ी सफलता हासिल की जहां इसने दुश्मन लड़ाकू विमानों के 80 प्रतिशत पैकेज को मार गिराया। अन्य विमानों को इसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जिससे उनके मिशन रद हो गए। यु रक्षा मिसाइल प्रणाली एस-400 को अब भारतीय वायुसेना भगवान कृष्ण के शक्तिशाली चक्र के नाम पर सुदर्शन कहती है।

नई दिल्ली। सुदर्शन एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने हाल ही में एक अभ्यास में बड़ी सफलता हासिल की, जहां इसने 'दुश्मन' लड़ाकू विमानों के 80 प्रतिशत पैकेज को 'मार गिराया'। अन्य विमानों को इसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनके मिशन रद हो गए।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा एक थिएटर में किया गया था, जहां सैन्य बल ने लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के अपने एक स्क्वाड्रन को तैनात किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा मिसाइल प्रणाली के बल में पूर्ण एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया था।

भारतीय वायुसेना ने अब इस प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया है, जिसके तीन स्क्वाड्रन पहले ही शामिल किए जा चुके हैं और 2026 में दो और की आपूर्ति होने की उम्मीद है। भारतीय पक्ष ने अनुरोध किया है कि रूस इन प्रणालियों की आपूर्ति में तेजी लाए।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि अभ्यास के दौरान एस-400 हथियार प्रणाली की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए असली लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली एस-400 को अब भारतीय वायुसेना भगवान कृष्ण के शक्तिशाली चक्र के नाम पर सुदर्शन कहती है।

वायु रक्षा प्रणाली ने अभ्यास के दौरान 'दुश्मन' के 80 प्रतिशत विमानों को 'मार गिराया' और शेष बचे विमानों ने अपना मिशन रद कर दिया। इन विमानों का उद्देश्य भारतीय क्षेत्र में अपने लक्ष्यों पर 'हमला' करना था। उन्हें वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया।

देश में हर साल 2.5 फीसदी बढ़ रहे कैंसर के मामले, स्वास्थ्य मंत्री बोले- सरकार की निगरानी में हैं 131 दवाइयां

देश में कैंसर के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में बताया कि हर साल कैंसर के मरीजों की संख्या 2 .5 फीसदी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके सस्ते और सुलभ इलाज के लिए लगातार प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इससे जुड़ी 131 दवाइयों की लगातार निगरानी कर रही है।

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा को बताया कि भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल कैंसर के मामले करीब 2.5 प्रतिशत बढ़ रहे हैं। सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है कि कैंसर के मरीजों को उसका सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध हो। नड्डा ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान महामारी का रूप लेते जा रहे कैंसर पर आंकड़ों का ब्योरा देते हुए कहा कि पुरुषों को मुंह और फेफड़े का कैंसर अधिक हो रहा है, जबकि महिलाओं को स्तन कैंसर अधिकाधिक हो रहा है। हर साल कैंसर के करीब 15.5 लाख नए मामले पंजीकृत किए जाते हैं।

सरकार की निगरानी में हैं दवाइयां

उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की अनिवार्य 131 दवाओं की सूची है। यह सभी अनुसूची एक में हैं, जिनकी सरकार हमेशा निगरानी करती है और इनके दामों का निर्धारण करती है। आमतौर पर इन्हीं दवाओं का उपयोग किया जाता है। कीमतों के नियंत्रण के चलते मरीजों की करीब 294 करोड़ रुपये की बचत होती है।

नड्डा ने बताया कि सरकार दवाओं के परीक्षण के लिए पूरी व्यवस्था बनाए हुए है। इसी तरह, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत 70 साल से अधिक आयु के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का कवर देने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है।

'लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं'

उन्होंने बताया कि मौजूदा लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जाधव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्रता वाले परिवारों के सभी सदस्यों को उनकी जो भी उम्र हो इस योजना के तहत इलाज मिलेगा। इस योजना के तहत योग्य हर परिवार को पांच लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है।

विचार

कारगिल विजय में टोलोलिंग-हम्प की कहानी

ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर

हमने लगातार हमले जारी रखे और 8 जुलाई को हमने पूरे टाइगर हिल पर विजय पताका फहरा दी। इस लड़ाई में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की शौर्य गाथा आज हर बच्चा जानता है'

भारतवर्ष का मुकुट कहे जाने वाले हिमालय के आंचल में बसे हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक व सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। देवों की भूमि होने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि भी रहा है। हमेशा से यहां के बेटों ने भारत मां की रक्षा में अपना योगदान दिया है। यहां के हर एक गांव में शूरवीरों की शौर्य गाथा के किस्से-कहानी हर बच्चे की जुबान पर होते हैं और यही कहानियां बच्चों को शौर्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यही कारण है कि हिमाचल की जनसंख्या का एक बड़ा भाग भारतीय सशस्त्र सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत है। वर्तमान में भारत की सशस्त्र सेनाओं में हर 13 सैनिक में से एक सैनिक हिमाचल की भूमि से आता है। स्वतंत्रता से अभी तक चार परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश से ही है। इन किस्से कहानियों में से एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है कारगिल युद्ध की। इसी कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के दो वीरों, कैप्टन विक्रम बत्रा और सिपाही संजय कुमार ने परमवीर चक्र का सर्वोच्च सम्मान अर्जित किया था। आज हमारा राष्ट्र कारगिल विजय के 25 साल पूरा होने पर रजत जयंती मना रहा है। हर वर्ष 26 जुलाई को मैं दराज कारगिल में जाकर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज से 25 वर्ष पूर्व स=1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के भरोसे की हत्या की थी और कारगिल, दराज और बटालिक के इलाकों में घुसपैठ करके अपना कब्जा कर लिया था।

जैसे ही भारतीय सेना को इसका आभास हुआ, तभी से घुसपैठियों को मार भगाने की कवायद शुरू हो गई। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह कवायद एक भीषण युद्ध की शुरुआत है। मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर, जिसका मैं कमान अधिकारी था, उन दिनों कश्मीर घाटी के मानसबल इलाके में तैनात थी। वहां पर आए दिन हमारी आतंकवादियों से मुठभेड़ होती थी। तैनात होने के कुछ ही दिनों में हमने 19 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी हमें हमारे उच्च अधिकारियों से आदेश मिला कि पलटन को तुरंत दराज मूव करना है। दराज सेक्टर में दुश्मन ने टोलोलिंग, टाइगर हिल और मास्को घाटी में सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया था और दुश्मन लेह, लद्दाख व सियाचीन ग्लेशियर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सेना के मूवमेंट को बाधित कर रहा था। 18 ग्रेनेडियर को टास्क मिला कि टोलोलिंग की सभी चोटियों को हर कीमत पर दुश्मन से मुक्त कराया जाए। हमने एक बेहतर रणनीति के साथ टोलोलिंग पर बैठे दुश्मन पर धावा बोल दिया। उस समय दुश्मन की तादाद और उसकी तैयारी के विषय में सटीक सूचना का अभाव था। साथ ही हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई लडने के लिए जरूरी साजो-सामान और दूसरे सैनिक दस्तों, विशेषकर आर्टिलरी का बेहद अभाव था। यही कारण था कि हर दिन हमारा नुकसान हो रहा था। परंतु 18 ग्रेनेडियर के जांबाजों ने इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने हौसलों को मजबूत रखा और अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन पर लगातार हमले करते रहे।

22 मई को शुरू हुआ यह हमला 14 जून तक चला और इन 24 दिनों में हम सभी कठिन व दुर्गम चढ़ाई, खराब मौसम और दुश्मन की लगातार हो रही भीषण गोलाबारी का सामना करते रहे। इस लड़ाई में मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक हमले के दौरान, जिसे मैं स्वयं लीड कर रहा था, मेरे उपकमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर. विश्वनाथन को गोली लगी और उन्होंने मेरी ही गोद में दम तोड़ दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल आर. विश्वनाथन को उनके अदम्य साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अंततः 12 जून को हमने 2 राजपूताना राइफल्स के साथ मिलकर टोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया और साथ ही 14 जून को हम्प की महत्वपूर्ण चोटी पर विजय हासिल की।

टोलोलिंग की लड़ाई में हमारे दो अधिकारी, दो सूबेदार और 21 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 18 ग्रेनेडियर के शौर्य को देखकर सेना के उच्च अधिकारियों ने एक बार फिर हमें एक और महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा और यह था दराज सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण चोटी टाइगर हिल पर कब्जा करना। मैं और मेरी टीम एक बार फिर अपनी तैयारी में जुट गए। हमने टाइगर हिल का हरसंभव दिशा से रीकोनोसेन्स किया और सभी टुकडियों के कमांडरों के सुझाव को शामिल करते हुए एक बेहद सटीक रणनीति बनाई। तीन जुलाई की रात को हमने टाइगर हिल पर चौतरफा हमला बोल दिया और सबसे कठिन रास्ते को चुना। जिस तरफ से जाना नामुमकिन था, हमारी कंपनी और घातक प्लाटून ने टॉप पर पहुंचकर दुश्मन को एकदम भौंचक्का कर दिया। पूरी रात एक भीषण घमासान युद्ध हुआ और हम टाइगर हिल टॉप पर अपना फुटहोल्ड बनाने में सफल हुए। इसके बाद हमने लगातार हमले जारी रखे और 8 जुलाई को हमने पूरे टाइगर हिल पर विजय पताका फहरा दी। इस लड़ाई में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की शौर्य गाथा आज हर बच्चा जानता है जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में हमारी यूनिट के नौ नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।

लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से और कप्तान सचिन निंबालकर को वीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर ने कई शौर्य पदक जीतकर अपने आप में एक कीर्तिमान बनाया। जैसे ही टाइगर हिल पर हमने विजय पताका फहराई, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना में खलबली मच गई। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ युद्धविराम की गुहार लगाने अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पास भागे। परंतु हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान के आखिरी घुसपैठिए को हम भारत की सीमा से नहीं खदेड़ देते, युद्धविराम का सवाल ही नहीं उठता। कारगिल के इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 527 रणबांकुरों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जिनमें 52 योद्धा हमारे हिमाचल प्रदेश के थे। कारगिल की लड़ाई से एक बार फिर साबित हो गया था कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाएगा तो भारत की सशस्त्र सेनाएं उस दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमेशा मुस्तैद हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023